

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

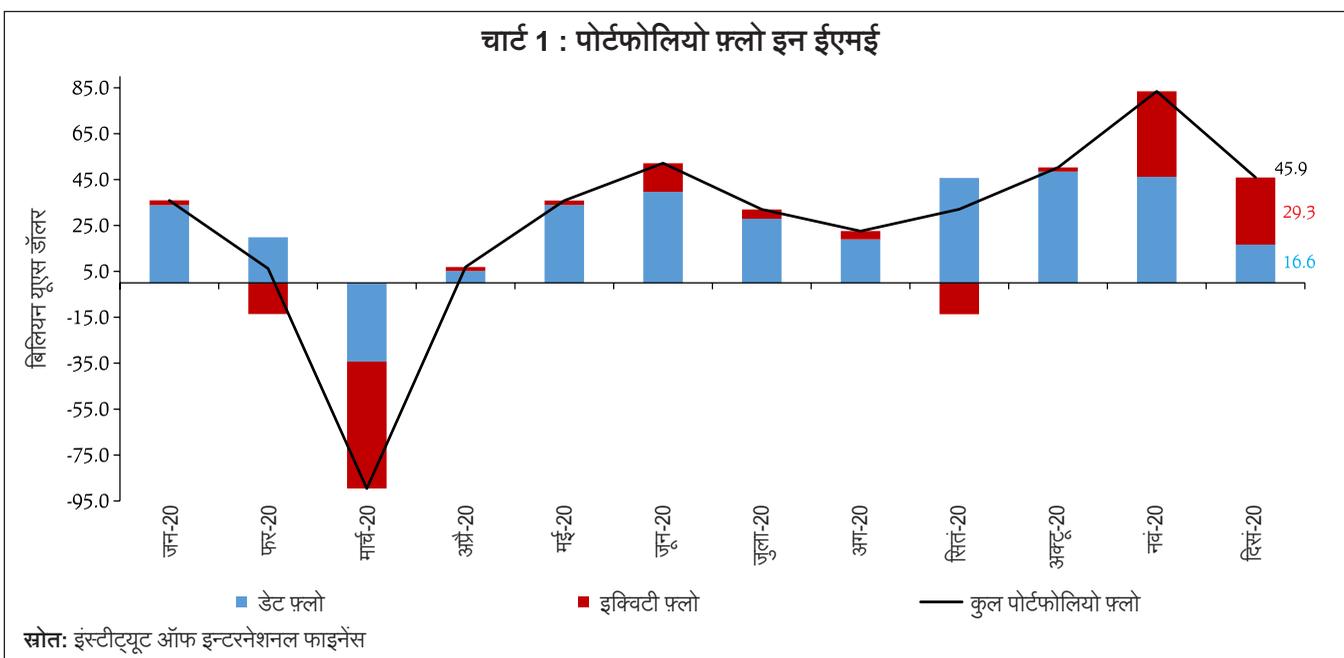
2020 एक ऐसा साल बन गया जिसमें सब कुछ बदल गया। वर्ष 2021 ने दुनिया भर के देशों के साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जीडीपी के सकारात्मक स्थिति को प्राप्त करने में विलंब और मुद्रास्फीति के लक्ष्य के करीब पहुंचने के साथ भारत में, मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य में हालिया बदलाव ने दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है। ईएमई द्वारा मजबूत पोर्टफोलियो इनफ्लो प्राप्त करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिकॉर्ड वार्षिक इनफ्लो प्राप्त करने के लिए भारत तैयार है को देखते हुए वित्तीय बाजार उत्साहित हैं।

वर्ष 2020 का समय भी क्या निकला! इसकी शुरुआत किसी अन्य वर्ष की ही तरह ही हुई बस वर्ष 2019 की तुलना में एक दिन अधिक था, चीन के वुहान में एक गीले बाजार से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को निमोनिया जैसी दिखने वाली बीमारी रिपोर्ट की गई। वर्ष के अंत तक, कोविड -19 ने आधिकारिक तौर पर 81 मिलियन लोगों को संक्रमित कर दिया था, और संभवतः 500 मिलियन और अधिक लोगों को डाइग्नोज ही नहीं किया गया (द इकोनॉमिस्ट 19 दिसंबर 2020)। इसके कारण 1.8

मिलियन लोगों की मौत हुई, लेकिन कई हजारों लोगों की मौत तो दर्ज ही नहीं हो पाई। दो विश्व युद्धों और स्पैनिश फ्लू के चलते कहीं अधिक मौतें हुईं, लेकिन कोविड -19 ने लोगों के दैनिक जीवन को इस तरीके से बदल दिया है जो इन घटनाओं में भी नहीं हुआ था। बचे हुए लाखों लोग अभी भी वायरस द्वारा छोड़े गए निशान और थकावट से जूझ रहे हैं, और दुनिया में पीड़ा, गरीबी (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 200 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में होंगे), असमानता और खतरे का माहौल है। बच्चों ने शिक्षा, ग्रेजुएट प्लेसमेंट, श्रमिकों को जबरन पलायन को झेला और सभी उम्र के लोगों को अकेलेपन का सामना करना पड़ा है।

बेरोजगारी बढ़ गई है और शेयर बाजारों पर भी ऐसा ही असर पड़ा है। विदेशी निवेशक उभरते बाजारों की दिशा में चले गए हैं - जबकि केवल मार्च में ही यूएस में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई), पोर्टफोलियो प्रवाह में तब से वापसी हुई है, जो कि नवंबर के महीने में 83.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और दिसंबर में यूएस \$ 16.6 बिलियन कर्ज में और यूएस \$ 29.3 बिलियन इक्विटी (IIF, 2021) (चार्ट 1) में। ईएमई में, चीन और भारत ने विकास की संभावनाओं के कारण प्रवाह को खींचा।

चार्ट 1 : पोर्टफोलियो फ्लो इन ईएमई



* इस लेख को देबा प्रसाद रथ, प्रज्ञा दास, आशीष थॉमस जॉर्ज, संगीता मैथ्यूज, अभिलाषा, कृष्ण मोहन कुशवाहा, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, अभिनंदन बोराड, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, शोभित गोयल, सक्षम सूद, अवनीश कुमार, ऋषभ कुमार, श्रीरूप सेनगुप्ता, राजस सरॉय, शशिधर एम.लोकरे और माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

अनुमानों के प्रति आशंकाओं के रूप में, COVID-19 (द इकोनॉमिस्ट, 9 जनवरी, 2021) के बिना विश्व उत्पादन कम से कम 7 प्रतिशत कम हो सकता है - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मंदी आई है, वर्ल्ड मर्चेन्डाइज ट्रेड 9.2% से (डबल्यूटीओ, 2020) और सेवाओं में विश्व व्यापार 15 प्रतिशत से (यूएनसीटीएडी, 2020)। इतिहास से पता चलता है कि सामाजिक अशांति एक महामारी के 14 महीने बाद बढ़ती है और 24 महीने (आईएमएफ, 2020) में चरम पर पहुंचती है। लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट नीले आसमान ने खुलासा किया कि तेजी से बढ़ते COVID-19 संकट के भीतर एक धीमी गति से चलने वाला जलवायु संकट है, जो लोकलुभावन इनकार के लिए अभेद्य है, इसकी विघटनकारी क्षमता वैश्विक है और कहीं अधिक महंगी है।

फिर भी, असंभव रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया इस शताब्दी में एक बार आने वाले वर्ष में दुनिया में शीघ्र ही कुछ घटित होने वाला है जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वर्ष 2021 आया दुनिया में 12 मिलियन से अधिक लोगों को वैक्सीन (चार्ट 2) की पहली खुराक दी जा चुकी थी। समाचार पत्रों ने बताया है कि अग्रिम अनुबंधों के माध्यम से विभिन्न देशों द्वारा वैक्सीन की 8.25 बिलियन खुराकें सुरक्षित की गई हैं (COVID-19 टीके दो-खुराक में दिये जाते हैं)।

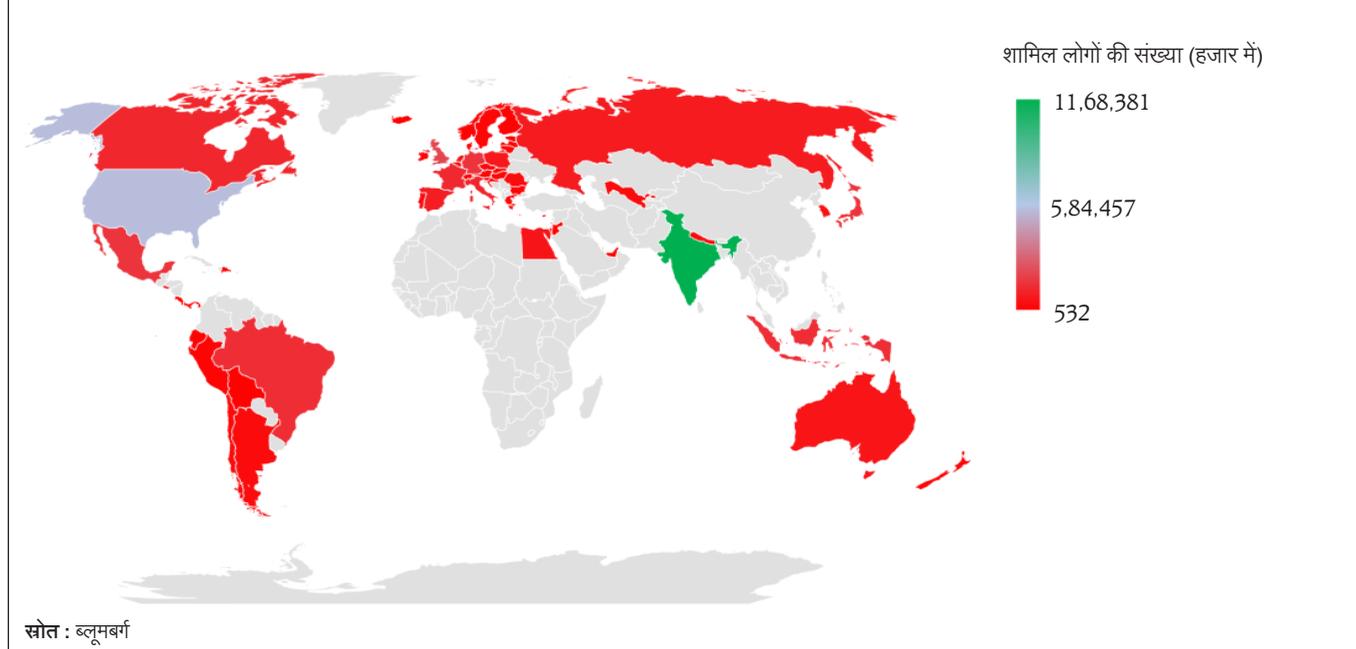
3 जनवरी, 2021 को भारत ने औपचारिक रूप से दो टीकों के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी और 16 जनवरी को,

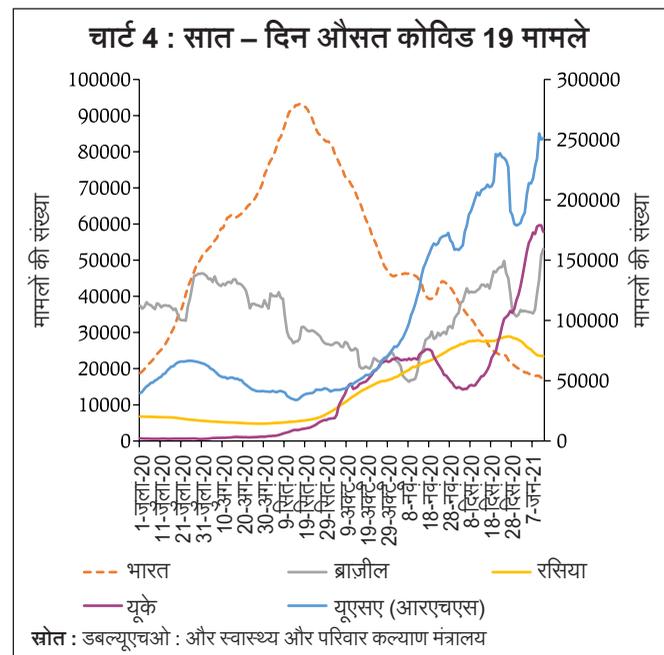
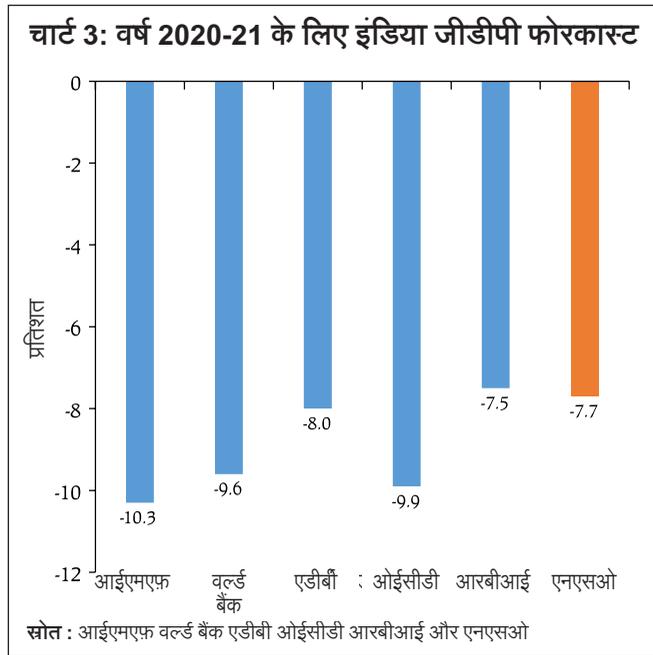
इसने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण ड्राइव शुरू की, जिसमें इस वर्ष लगभग 300 मिलियन लोगों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने की योजना थी। यह बताया गया है कि भारत ने 1.2 बिलियन अग्रिम खुराक प्राप्त की है, जो 85 प्रतिशत आबादी (ब्लूमबर्ग, 2020) को कवर करती है।

चार अन्य विशेषताएं हैं जिन्होंने भारत को दुनिया से अलग किया है जिससे यह संभावना बढ़ी है कि हमारी रिकवरी अधिकांश अनुमानों से आगे निकल सकती है, जैसा की इस लेख में लगातार बताया गया है। 27-संकेतक आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) (कुमार, 2020) ने तीसरी तिमाही : 2020-21 के लिए अपना नावकास्ट अपडेट किया है और दिसंबर 2020 के अंक में तिमाही की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 0.1 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 7 जनवरी को जारी 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों में भी परिलक्षित होता है, जिसमें 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान (-) 7.7 प्रतिशत के विरुद्ध (- अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 10.3 प्रतिशत और दिसंबर 2020 (चार्ट 3) में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा (-) 7.5 प्रतिशत है।

पहला, भारत अब तक COVID-19 की दूसरी लहर से बचने में सफल रहा है। इसके अलावा, सितंबर के मध्य से, भारत

चार्ट 2 : कौंटरेक्ट दिये गए कोविड वैक्सीन के डोज की संख्या

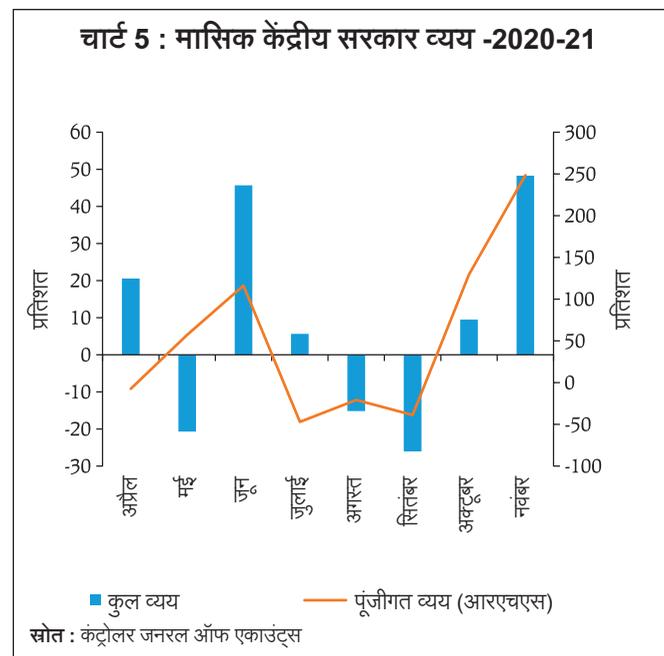


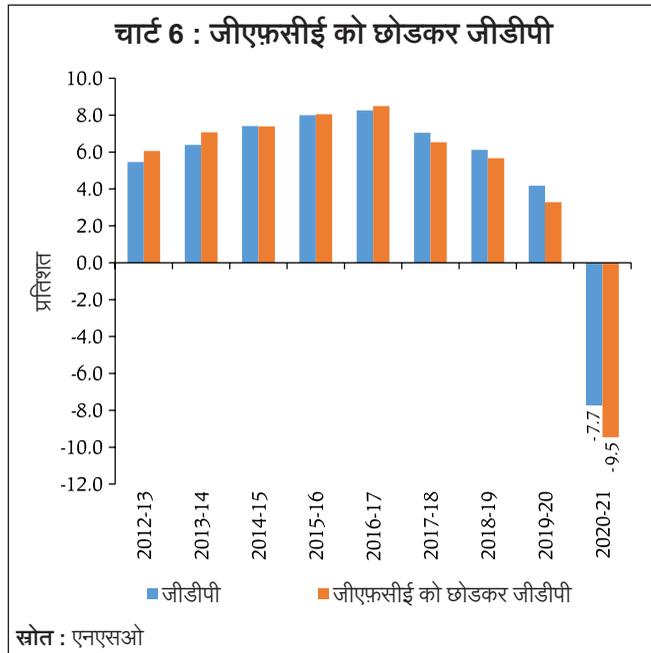


ने 'बेकहम की तरह इसे झुका दिया' - 2020 के अंत तक, सक्रिय मामलों की संख्या 17 सितंबर को 10,17,754 के शिखर से 2,54,254 तक गिर गई थी। भारत में रिकवरी दर सुधरकर 96.1 प्रतिशत हो गई है जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दर है। मृत्यु दर 1.4 प्रतिशत है, जो विश्व मृत्यु दर (2.2 प्रतिशत) से कम है, और एक लाख से अधिक संक्रमण वाले देशों (चार्ट 4) के मध्य दूसरा सबसे कम है।

जीडीपी को लगातार मूल्यवान प्रति-चक्रिय समर्थन प्रदान किया है। इस समर्थन के बिना, 2017-18 में 7.0 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि केवल 6.5 प्रतिशत रही होती, जबकि यह 2018-19 में 6.1 प्रतिशत के बजाय 5.7 प्रतिशत रही होती और 4.2 प्रतिशत के बजाय 3.3 प्रतिशत होती, पहली तिमाही : 2019-20 (चार्ट 6)। पहली तिमाही: 2020-21 में जब COVID -19 के

दूसरा, चार महीने के अंतराल के बाद, जिसके दौरान केंद्र सरकार का कुल खर्च संकुचन में चला गया या मौन रहा, इसने नवंबर 2020 में रिकवरी को फिर से शुरू किया, जो साल-दर-साल के आधार पर 48.3 प्रतिशत बढ़ गया। इस व्यय बढ़ोत्तरी के भीतर, विकास को पोषित करने वाला पूंजीगत व्यय एक तीन महीने के संकुचन में चला गया और यह 248.5 प्रतिशत बढ़ गया जो कि आत्मा निर्भर 2.0 घोषणाओं के अनुसरण में कैपेक्स के लिए राज्यों को किए जाने वाले अंतरण में वृद्धि के चलते इसके आधे के करीब पहुँच गया था (चार्ट 5)। उप-राष्ट्रीय स्तर पर, 20 राज्यों के लिए जानकारी बताती है कि 8 महीने तक लगातार अनुबंध करने के बाद अक्टूबर 2020 के दौरान पूंजीगत व्यय में वृद्धि सकारात्मक रही। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, क्योंकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीडी) ने चौथी तिमाही : 2016-17 से

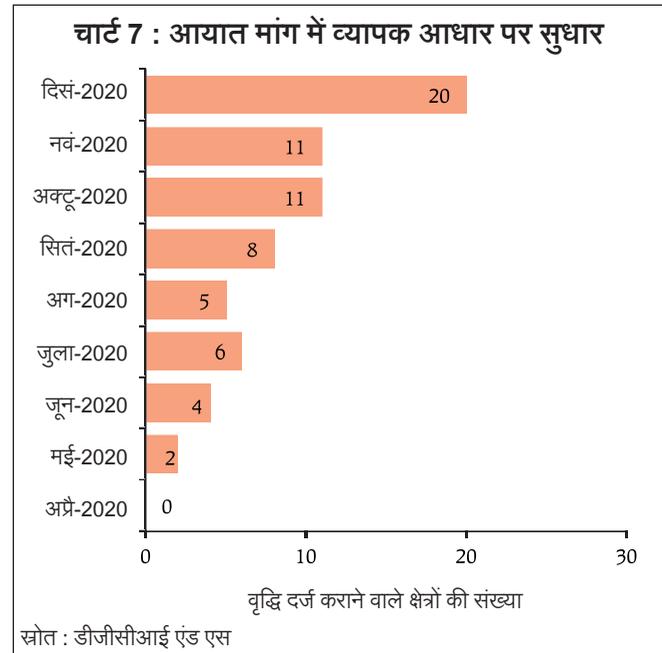




कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में एक अभूतपूर्व 23.9 फीसदी की गिरावट आई थी, जीएफसीई ने 29.3 प्रतिशत की और भी तेज़ गिरावट को रोका था।

तीसरा, माल आयात अंत में लगातार 9 महीनों में संकुचन से बाहर आया और दिसंबर 2020 (चार्ट 7) में 7.6 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि हुई। आयात में पलटाव व्यापक था, जिसमें 30 में से 20 प्रमुख वस्तुओं ने विस्तार दर्ज किया। इनमें से कई वस्तुएं आपूर्ति श्रृंखलाओं में मध्यवर्ती वस्तुओं की प्रकृति की हैं, जो घरेलू औद्योगिक गतिविधि और आयात-गहन निर्यात के लिए अच्छी तरह से विकसित होती हैं। इससे पता चलता है कि घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था की मृतप्राय क्षमता वापस आ रही है। पूंजी प्रवाह में वृद्धि, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में देख रही है, यहां से हो सकता है कि यह निवेश और विकास का समर्थन करें और आरक्षित संचय के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली घरेलू बचत के बजाय घरेलू बचत बढ़ा सकती है। भारत के भुगतान शेष के टेल वैगिंग दि डॉग¹ के दिन अंततः समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

¹ भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, यह व्यापारिक व्यापार खाता है जो अपने शेष भुगतान पर हावी है, और पूंजी खाता आमतौर पर एक छोटी वित्तपोषण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में, हालांकि, विशेष रूप से 2019 के बाद से, भारत में शुद्ध पूंजी प्रवाह एक स्तर तक बढ़ गया है, जिसमें वे शेष राशि के भुगतान में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'टेल वैगिंग दि डॉग' की घटना होती है। आगे पढ़ने के लिए, कृपया <https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/28/conf28h.pdf?la=en> का संदर्भ लें।



चौथा, बैंक क्रेडिट मांग 6 प्रतिशत से अधिक की गति से बढ़ी है, जिसने उप-6 प्रतिशत वृद्धि के 5 महीने के समय को उलट दिया है। कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और परिवहन, व्यापार और पर्यटन के नेतृत्व में सेवा क्षेत्र में मजबूत ऋण प्रवाह के शीर्ष पर क्रेडिट चक्र को गतिशीलता प्रदान की है।

इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में इस लेख के शेष भाग को पांच खंडों में सृजित किया गया है। खंड II संक्षेप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को दर्शाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित आवेग खंड III में निहित हैं। खंड IV वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जबकि अंतिम खंड कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

II. ग्लोबल सेटिंग

यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए लॉकडाउन क्रिसमस था, क्योंकि वायरस के एक नए और अधिक वायरल स्ट्रेन ने और दूसरी / तीसरी लहर के तेजी से फैलने ने न केवल इस समय हर्षोल्लास को बल्कि वैक्सीन द्वारा उत्पन्न आशावाद को भी हतोत्साहित किया। कुछ ईएमई में महामारी से होने वाले व्यवधान पहले से प्रत्याशित रूप से अधिक गंभीर हो गए हैं, जिसका खामियाजा कमोडिटी निर्यातकों को भुगताना पड़ रहा है। कुल मिलाकर, 2020 के मध्य से शुरुआती रिबाउंड के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी धीमी हो गई है। विनिर्माण

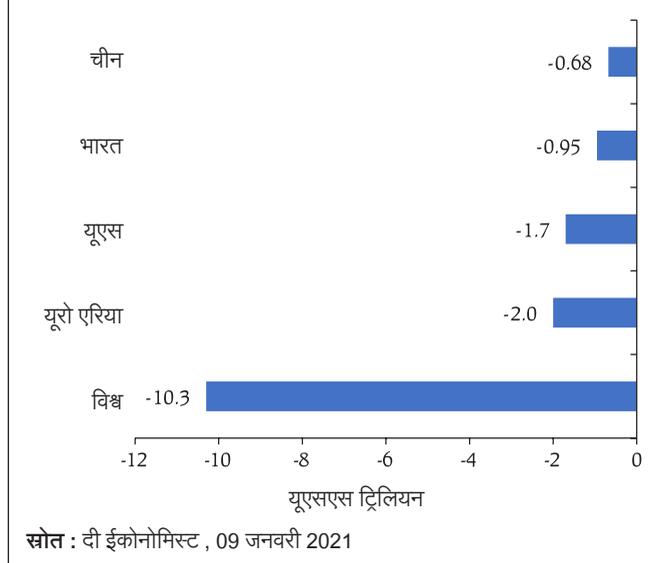
गतिविधि और व्यापार में सुधार को अवसादग्रस्त सेवा क्षेत्रों द्वारा हतोत्साहित कर दिया गया है। वैश्विक निवेश में गिरावट की घोषणा कर दी गई है। जबकि, वित्तीय स्थितियां बेहद आसान हैं, वित्तीय कमजोरियां बढ़ रही हैं, जिससे यह डर बढ़ रहा है कि कोविड -19 संकट अंततः वित्तीय संकट में बदल जाएगा (रेनहार्ट, 2020)। जनवरी के आते ही, लक्ष्यों के अद्यतनीकरण का समय आ गया है, और विश्व बैंक इसका नेतृत्व कर रहा है। 5 जनवरी, 2021 को जारी अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाओं (जीडीपी) में, अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2020 में 4.3 प्रतिशत घट गई है - ईई 5.4 प्रतिशत; ईएमई एक्स -चीन 5.0 प्रतिशत से (तालिका 1)। 2021 में, यह अनुमान है कि वैश्विक उत्पादन में 4 प्रतिशत वृद्धि होगी, लेकिन पूर्व-महामारी अनुमानों से 5.3 प्रतिशत नीचे या यूएस \$ 4.7 ट्रिलियन डॉलर से कम रहेगी। ईई और ईएमई और एक्स -चीन मोटे तौर पर विकास प्रोफाइल में एक जैसे दिखेंगे, 3.3-3.4 प्रतिशत के मामूली विस्तार के साथ। भारत के संबंध में 5.4 प्रतिशत विस्तार की उम्मीद है, जो उसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड से परिलक्षित होता है। ऐसा अनुमान है कि COVID-19 से 2020 और 2021 (चार्ट 8) में विश्व जीडीपी में 10.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच, भारत को यूएस \$ 950 बिलियन का सबसे बड़ा नुकसान होगा (द इकोनॉमिस्ट, 9 जनवरी, 2021)। महामारी एक तरफ ऋण के संचय के आसपास के जोखिमों को बढ़ा सकती है और दूसरी

तालिका 1 : जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिन्दा ईई और ईएमई

देश	2020		2021	
	जून 2020	जन 2021	जून 2020	जन 2021
 विश्व	-5.2	-4.3	4.2	4.0
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ				
 यूएस	-6.1	-3.6	4.0	3.5
 यूरो एरिया	-9.1	-7.4	4.5	3.6
 जापान	-6.1	-5.3	2.5	2.5
उदीयमान मार्केट अर्थव्यवस्थाएँ				
 ब्राज़ील	-8.0	-4.5	2.2	3.0
 रूस	-6.0	-4.0	2.7	2.6
 भारत	-3.2	-9.6	3.1	5.4
 चीन	1.0	2.0	6.9	7.9
 साउथ अफ्रीका	-7.1	-7.8	2.9	3.3

स्रोत : विश्व बैंक

चार्ट 8 : महामारी के पूर्व किए गए अनुमानों की तुलना में 2020 -21 में जीडीपी में कमी



ओर संभावित उत्पादन में लंबे समय तक मंदी का कारण बन सकती है। नतीजतन, अनुमानों के लिए नकारात्मक जोखिम की भविष्यवाणी करते हैं।

मूल्य की स्थिति पर, अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, निम्नलिखित में से ईई और उपरोक्त में से कई ईएमई (तालिका 2)। खाद्य पदार्थों की कीमतों में विशेष रूप से ईएमई में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि संयुग्मन में काम कर रहे कारकों के संगम के कारण है यथा सरकारों ने अपने खाद्य भंडार बढ़ाने शुरू कर दिये हैं, लॉजिस्टिकल समस्याएँ और ला नीना लैटिन अमेरिका² में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक 2020 में 3.1 प्रतिशत बढ़ गया जिसके साथ मासिक सूचकांक दिसंबर में छह साल के उच्च स्तर पर था।

² <https://www.ft.com/content/20a5e763-4d2f-4872-a1f9-7852a5be6d68>

तालिका 2 : मुद्रास्फीति अनुमान 2020 – दिसंबर में चुनिन्दा एई और ईएमई अनुमान

(प्रतिशत)

देश	अनुमान	लक्ष्य / नियंत्रण सीमा का मध्य बिन्दु अथवा वर्ष 2020 के लिए टोलरेंस बैंड
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ		
 यूएस	1.2	2.0
 यूरो एरिया	0.2	2.0
 कनाडा	0.6	2.0
उदीयमान मार्केट अर्थव्यवस्थाएँ		
 ब्राजील	4.3	4.0
 रूस	4.6 to 4.9	4.0
 भारत	6.6*	4.0
 थाईलैंड	-0.9	2.0
 इंडोनेसिया	1 प्रतिशत से कम	3.0

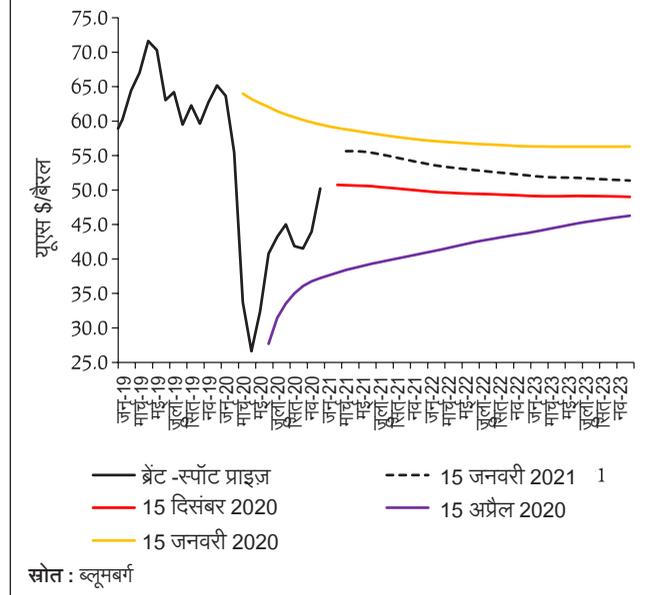
*: एक्चुअल्स (जून-सितंबर 2020) के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित औसत और 4 दिसंबर 2020 के एमपीसी विवरण में ति. 3 और ति. 4 : 2020-21 के लिए अनुमान

स्रोत : केंद्रीय बैंक वेबसाइट

इस बीच, पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) प्लस के संगठन द्वारा वैक्सीन के मोर्चे पर सकारात्मक विकास और उत्पादन में कटौती के विस्तार की वजह से दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रही। दिसंबर में यूएस \$ 49.9 प्रति बैरल के औसत पर, ब्रेंट दिसंबर में 15.5 प्रतिशत महंगा था (चार्ट 9)। हालांकि, 2020 में औसत ब्रेंट की कीमत 2019 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत कम थी। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2020 में तेल की मांग में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

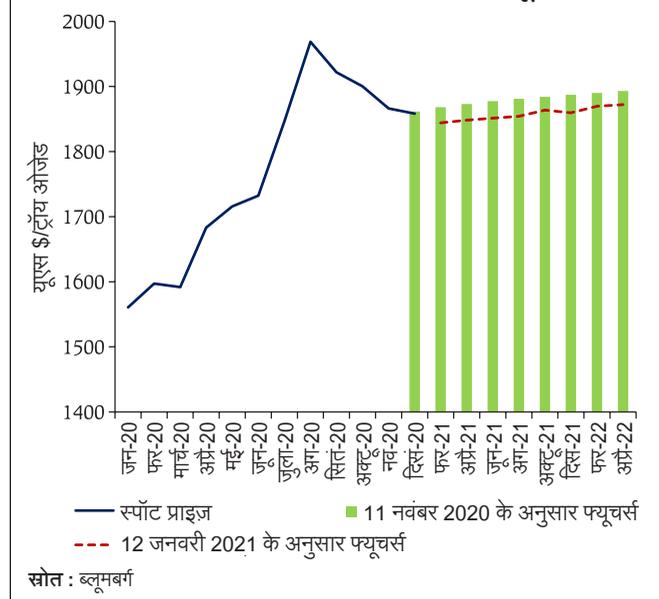
सोने ने एक अभूतपूर्व साल की शुरुआत की, जिसमें अगस्त में बुलियन कीमतों में 25.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ, पिछले वर्ष

चार्ट 9 : ब्रेन्ट फ्यूचर्स



में 18.3 प्रतिशत चढ़ने के बाद सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। सेफ हैवेन डिमांड और अभूतपूर्व मौद्रिक एकोमोडेशन ने बुलियन को 2020 में एक शीर्ष प्रदर्शन वाली परिसंपत्ति बना दिया। 2021 सेफ हैवेन डिमांड कम होने के कारण सेल ऑफ और डॉलर की मजबूती (चार्ट 10) के कारण सोने की कीमतें सही हो गई हैं। सोने की महिमा के आधार पर, चांदी का 2020 में भी

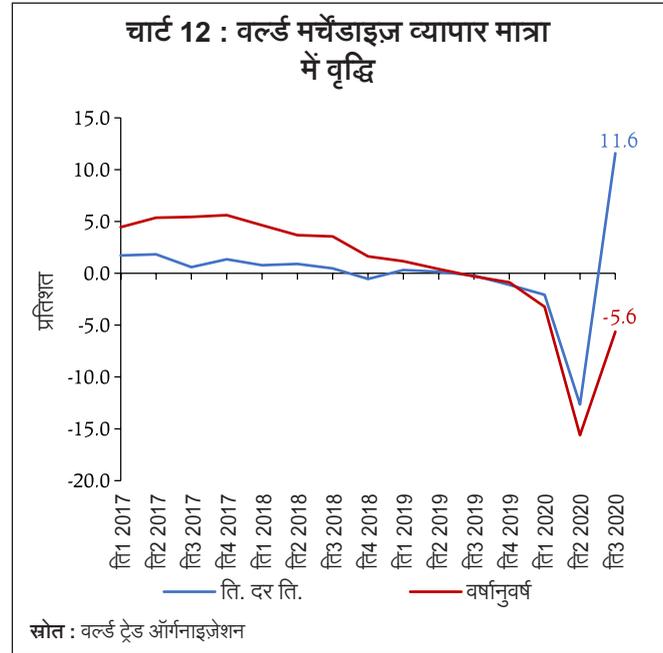
चार्ट 10 : गोल्ड प्राइजेस -स्पॉट एंड फ्यूचर्स



अच्छा साल रहा। बेस मेटल्स, जिन्होंने साल के शुरुआती महीनों में तेज गिरावट देखी थी, एच 2:2020 में मजबूती से उबरने के साथ ही साल का अंत हुआ।

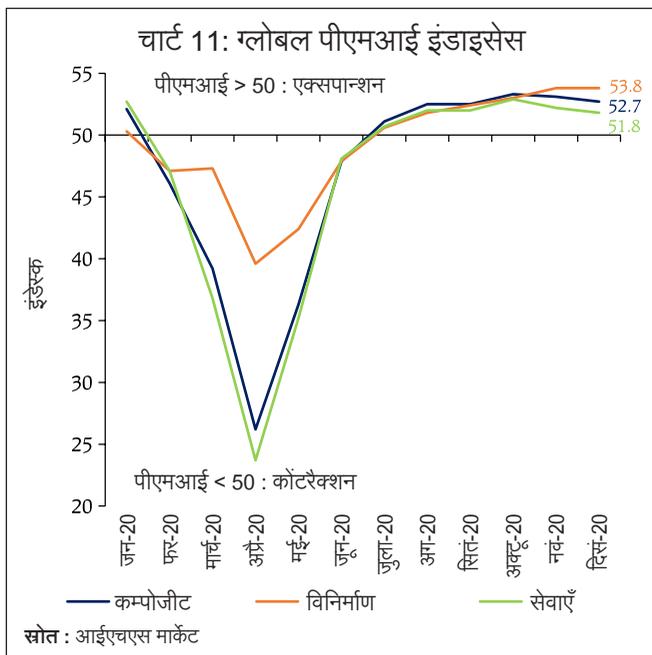
वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) दिसंबर में 52.7 पर आ गया, जो मुख्य रूप से सेवाओं के पीएमआई के पांच महीने के निचले स्तर तक अर्थात 51.8 पर आने के कारण था। अच्छी खबर यह है कि यह पूरे एच 2: 2020 के लिए विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है। दिसंबर में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई ने नवंबर के 33 महीने के उच्च स्तर को बनाए रखा। फरवरी और जून (चार्ट 11) के बीच भारी गिरावट के बाद औद्योगिक उत्पादन एच 2: 2020 में लगातार बढ़ा है। इस बीच, मूल्य गति लगातार बढ़ती जा रही है - मई 2011 के बाद से दिसंबर में इनपुट कीमतें अपनी उच्चतम गति से बढ़ीं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व व्यापार माल की मात्रा में पिछली तिमाही में 12.7 प्रतिशत के संकुचन के बाद ति.3: 2020 में 11.6 प्रतिशत का क्रमिक सुधार हुआ। हालाँकि, ति. 3 में वर्षानुवर्ष आधार (चार्ट 12) पर 5.6 प्रतिशत का संकुचन था। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि 2020 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान व्यापारिक व्यापार की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत कम थी,



यद्यपि यह अभी भी 2020 में समग्र विश्व व्यापार में विश्व व्यापार संगठन के 9.2 प्रतिशत के संकुचन के अनुमान की तुलना में, अनुकूल है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2020 में विश्व व्यापार की मात्रा (माल और गैर-कारक सेवाएँ) में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आई है और व्यापार अनिश्चितता का स्तर प्रवृत्ति से अधिक बना हुआ है जो कि हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जैसी गतिविधियों के बावजूद है।

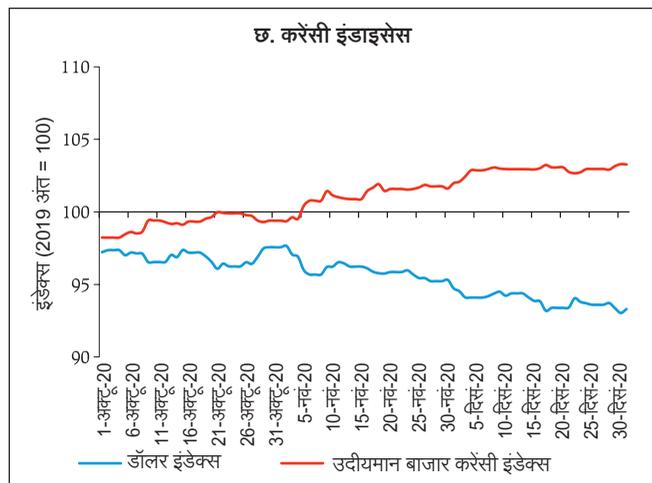
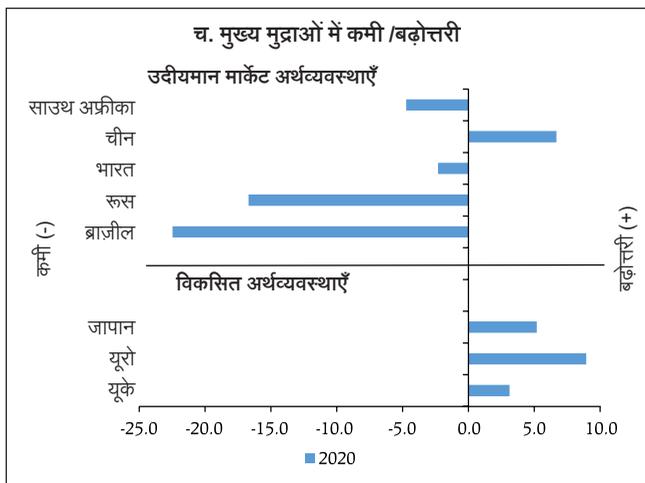
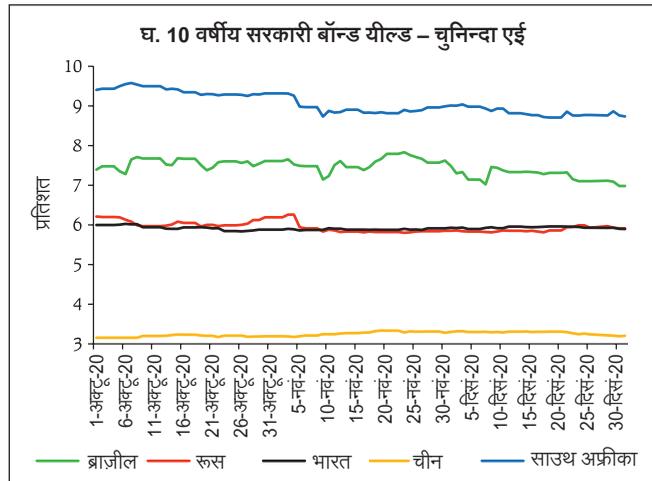
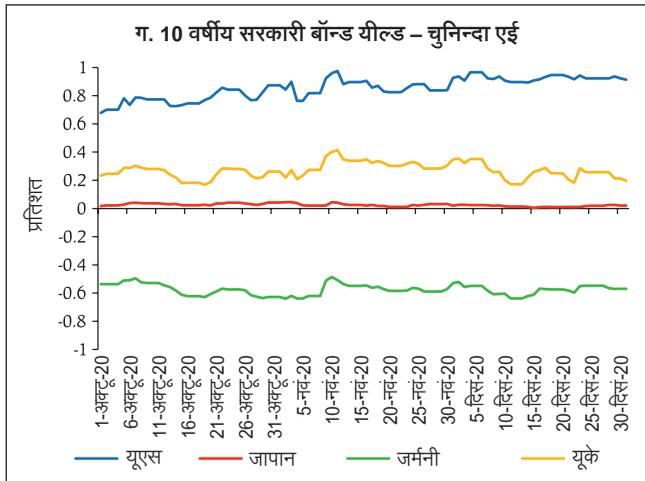
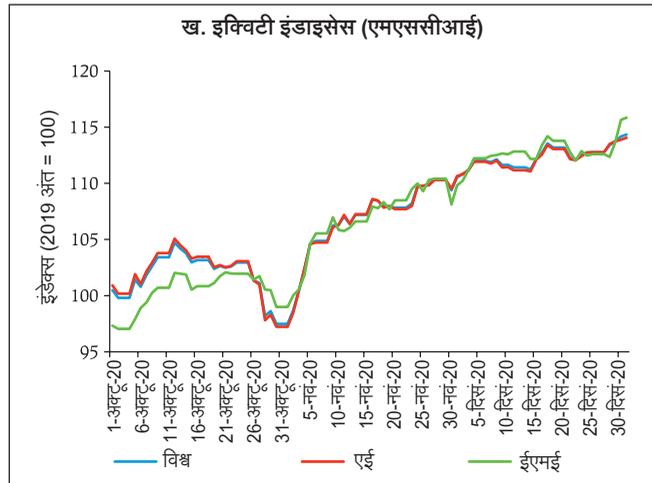
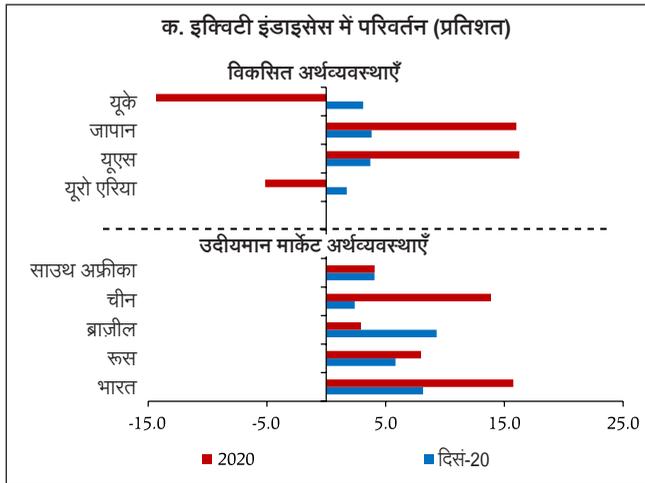
मैक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोण में सुधार और तेजी से टीकाकरण के कारण इक्विटी बाजारों में नवंबर 2020 में रिकॉर्ड लाभ हुआ, इस संबंध में ब्रेक्सिट सौदे और दिसंबर के अंत के लिए अमेरिकी प्रोत्साहन का भी लाभ हुआ। मूल्यांकन में वृद्धि के बावजूद, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, थाईलैंड और चिली के शेयर बाजारों ने लाल रंग में साल का अंत किया। दूसरी ओर, ईएमई के शेयर बाजारों में बढ़ते हुए लाभ के कारण मजबूत पोर्टफोलियो प्रवाह हुआ। दिसंबर में ईएमई में कुल पोर्टफोलियो प्रवाह यूएस \$ 45.9 बिलियन था, और पूरे वर्ष के लिए, वे यूएस \$ 313.6 बिलियन (आईआईएफ, 2021) थे। पुनर्मुद्रास्फीति व्यापार और रिस्क ऑन सेंटीमेंट्स ने एई में बांड यील्ड को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर, ईएमई में बांड यील्ड में अनुकूलता बनी रही, जो कि मजबूत



पोर्टफोलियो प्रवाह (चार्ट 13) को परिलक्षित करता है। कोविड-19 वैक्सीन द्वारा प्रदान किए गए अपबीट आउटलुक ने दिसंबर में अमेरिकी डॉलर को नीचे की स्लाइड पर रखा और आई और

ईएमई की मुद्राओं को बहु-वर्षीय ऊँचाइयों तक पहुंचाया। कुल मिलाकर, दिसंबर में डॉलर सूचकांक कमजोर होकर 2.1 प्रतिशत पर आ गया, जो वर्ष 2020 में 6.7 प्रतिशत कम हो गया था। एक

चार्ट 13 : वित्तीय बाजार गतिविधियां

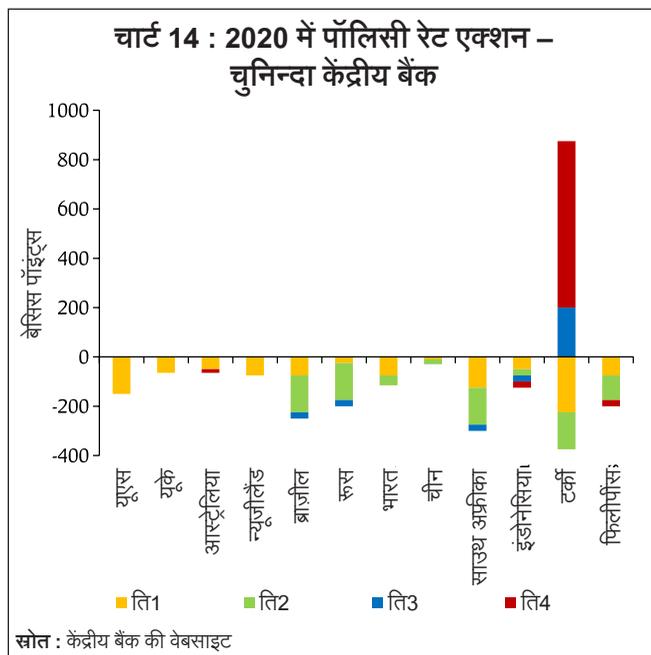


स्रोत : ब्लूमबर्ग और थॉमसन रायटर्स

कोरोलरी के रूप में, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स (MSCI-EM) सूचकांक दिसंबर में 1.6 प्रतिशत और पूरे वर्ष में 3.3 प्रतिशत की बढ़त की। वर्ष 2021 में अब तक, डॉलर मजबूत हुआ है, और यह ज्यादातर यूरो जैसी आई मुद्राओं की तुलना में हुआ है।

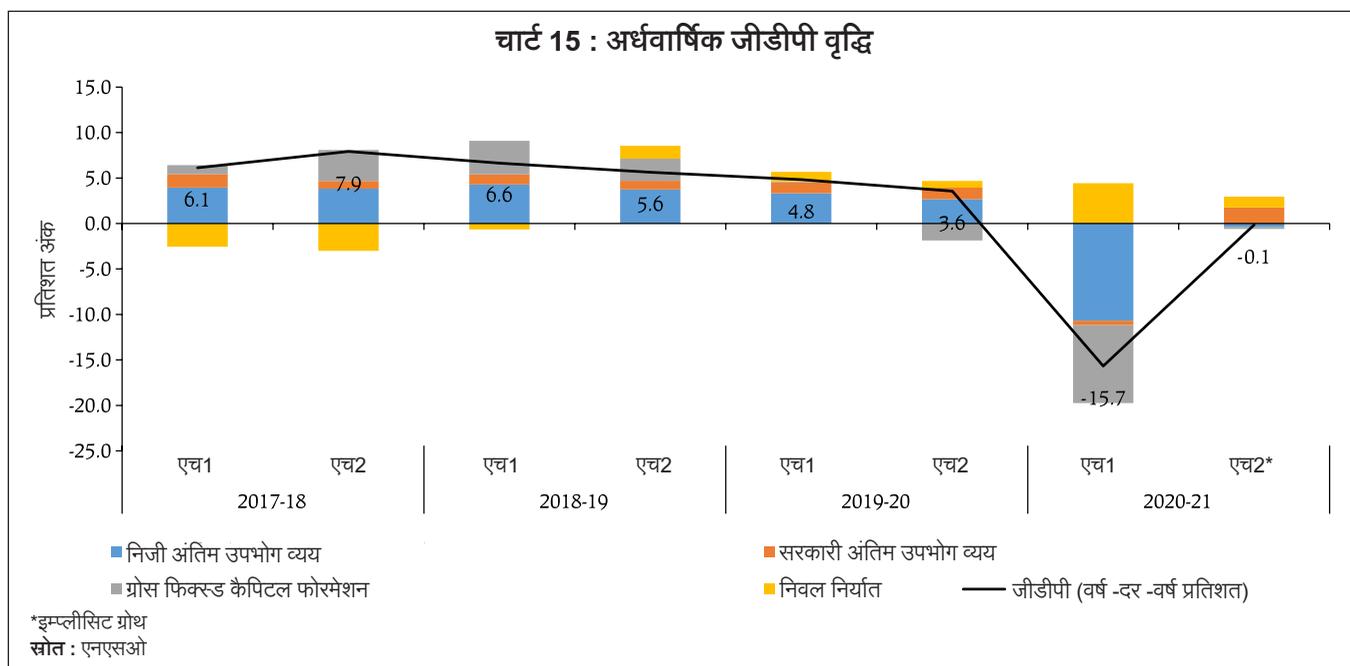
मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, प्रचुर मात्रा में चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों पर रोक की केंद्रीय बैंकों के बीच सामान्य प्रवृत्ति के बीच, दिसंबर में यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन का और विस्तार किया गया था। फेडरल रिजर्व ने निरंतर आस्तियों की खरीद के लिए मार्गदर्शन दिया जब तक कि वह अधिकतम रोजगार और मूल्य स्थिरता लक्ष्यों के संबंध में प्रगति न कर ले। इसके विपरीत, तुर्की के केंद्रीय बैंक ने उच्च और बढ़ती मुद्रास्फीति (चार्ट 14) से जूझते हुए, चार महीनों में तीसरी नीति दर वृद्धि को अंजाम दिया।

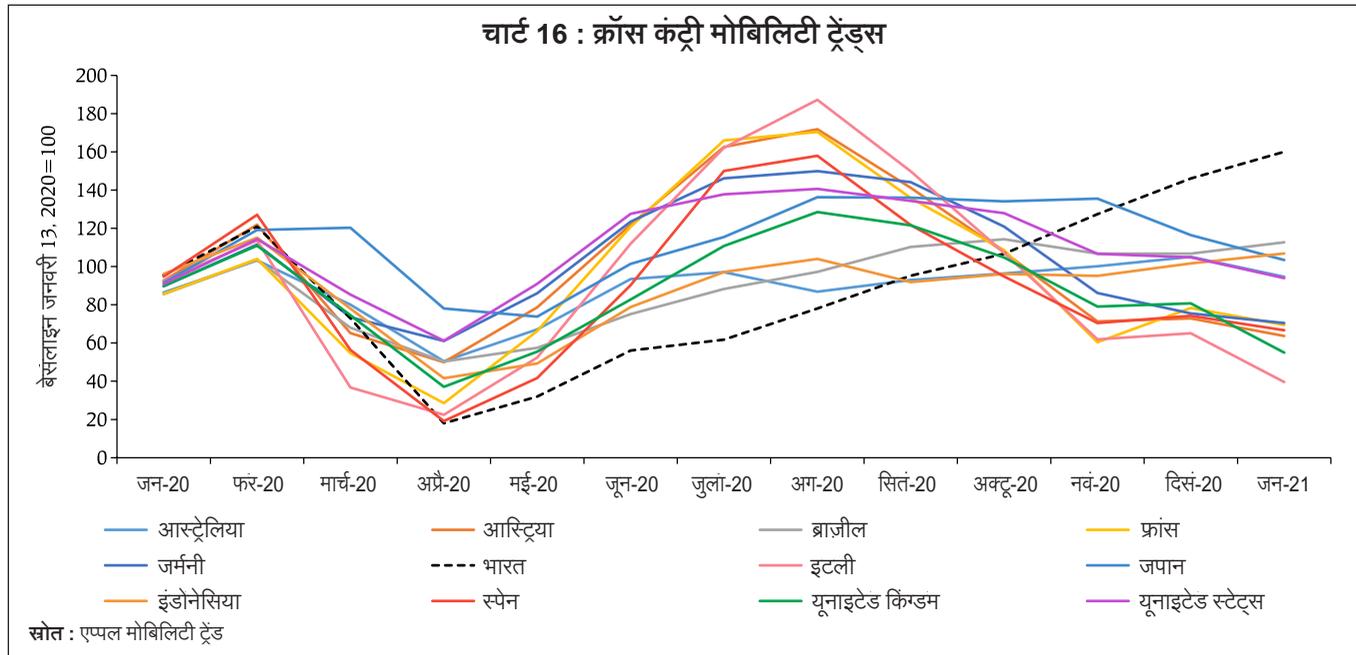
जैसा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था नए साल में कदम रख रही है, निकट भविष्य में काफी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आई संक्रमण और कड़े लॉकडाउन और वायरल प्रकोप के साथ संघर्ष करेगा और 2017 में देखे गए गरीबी के स्तर पर ईएमई आ सकती है।



III. घरेलू विकास

इस आलेख में जो अनुमान लगाया जा रहा था वह 7 जनवरी की जीडीपी रिलीज में निहित है - एक और लहर के आने की बात को छोड़ते हुए, सबसे खराब समय हमारे पीछे है (चार्ट 15)। हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि बहाली



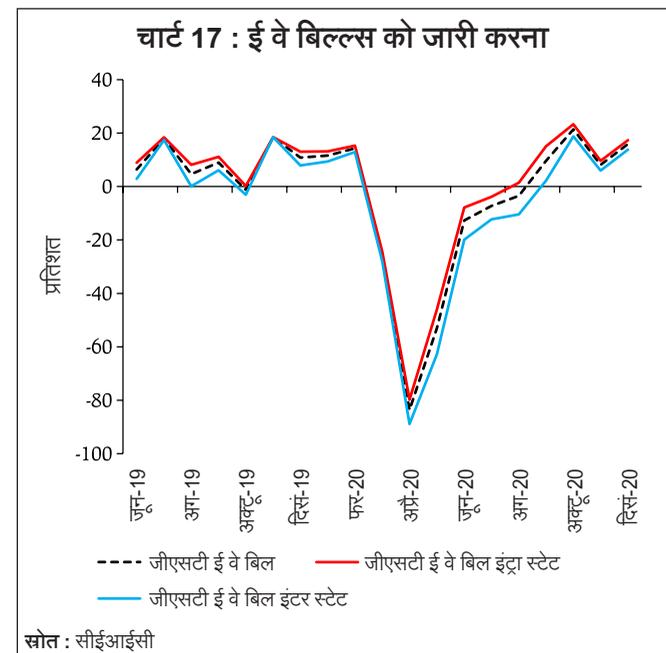


अपने कर्षण में मजबूत हो रही है और जल्द ही हमारे असंतोष की सर्दी को शानदार गर्मी³ बना दिया जाएगा। क्रॉस-कंट्री तुलना इंगित करती है कि भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं (चार्ट 16) से आगे बढ़ रहा है। छह सबसे बड़े राज्य - महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल - ने सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य प्रतिशत में 87 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो महामारी (मिंट ट्रैकर) में अब तक का सबसे अच्छा स्तर है। ई-वे बिल जारी करने में परिलक्षित होने वाली घरेलू ट्रेडिंग गतिविधि तेज गति से बढ़ी, यहां तक कि उच्च आधार पर, 15.9 प्रतिशत की वृद्धि वर्षानुवर्ष - आंतर-राज्य में 17.3 प्रतिशत और अंतर-राज्य में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तव में, दिसंबर 2020 के दौरान जारी किए गए ई-वे बिलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, यह सुझाव देते हुए कि अब त्योहार के खर्चों के सामयिक टेलविन्ड्स पर रिकवरी नहीं होती है, बल्कि यह फीनिक्स की तरह एक आंतरिक गति से बढ़ रहा है (चार्ट 17)।

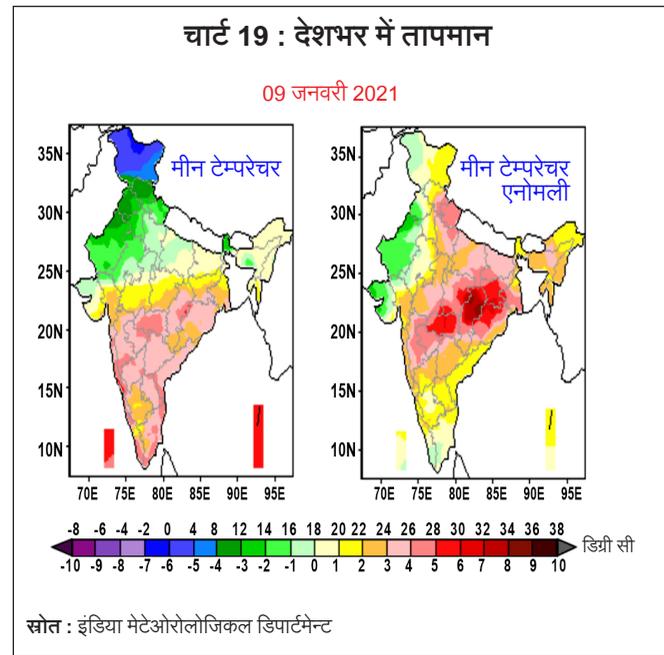
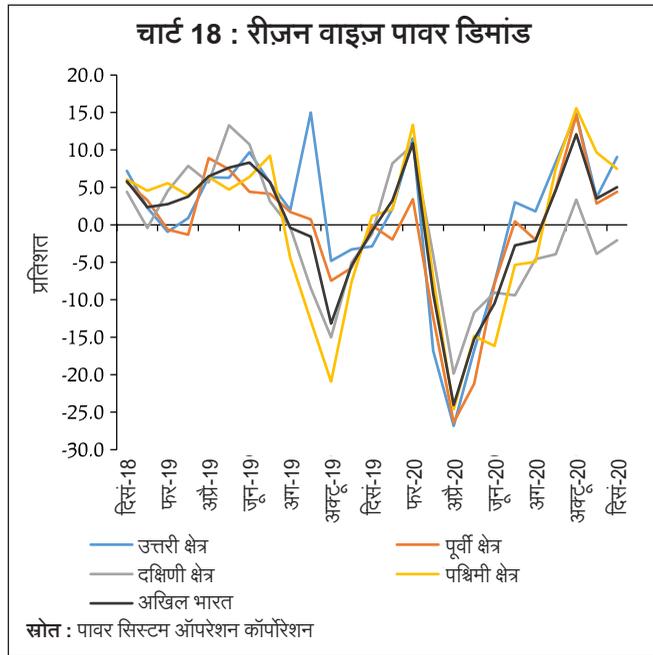
सकल मांग

सकल मांग की स्थितियों ने हाल के लाभ को समेकित किया है या दिसंबर 2020 में गति को मजबूत किया है। बिजली की खपत में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि वर्षानुवर्ष हुई है, जिसने चौथे

क्रमिक महीने (चार्ट 18) में अपनी वृद्धि को बनाए रखा है। दिसंबर में उत्तरी और मध्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश (15 प्रतिशत), राजस्थान (12 प्रतिशत), बिहार (14 प्रतिशत), पंजाब (12 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (10 प्रतिशत) ने हीटिंग लोड बढ़ने के कारण बिजली की मांग में वृद्धि का अनुभव किया। एक असामान्य रूप से तीव्र सर्दियों के रूप में बहु-वर्षीय चढ़ावों के साथ पारा का स्तर गिर गया, जिसमें प्रशांत के पानी को ला नीना ने ठंडा किया



³ रिचर्ड तृतीय में विलियम शेक्सपियर से लिया गया है

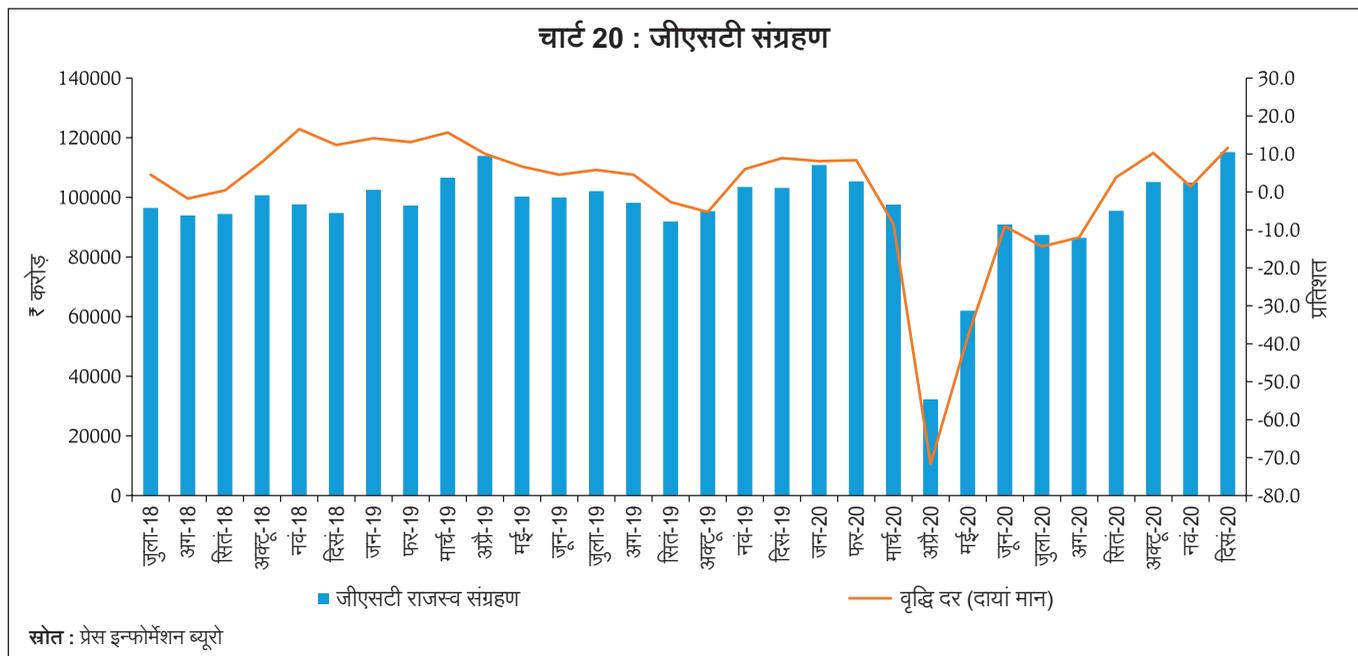


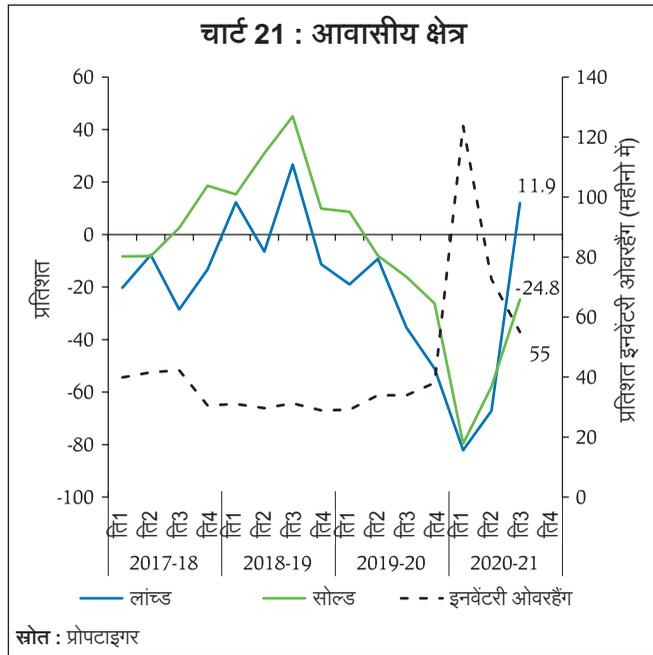
और ऊपरी भारत के अधिकांश हिस्सों में एक शीत लहर ने जोर पकड़ लिया, और इन राज्यों में छिटपुट बेमौसम बारिश भी हुई (चार्ट 19)।

घरेलू खर्च तेजी से सामान्य हो रहा है, और इसी के अनुरूप, माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रह दिसंबर में रुपये 1.15 लाख करोड़ के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसने तीसरे महीने के लिए रुपये 1 लाख करोड़ की

‘बाधा’ को भी लगातार तोड़ दिया, और एक साल पहले (चार्ट 20) से 11.6 प्रतिशत अधिक। व्यावसायिक गतिविधि एक 'अनलॉक' मोड में पुनर्जीवित हो रही है, जिसे एक सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग सिस्टम द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है।

उपभोक्ताओं का विश्वास पुनःस्थापित हो रहा है। रीफिनिटिव -इप्सोस उपभोक्ता कंज्यूमर सेंटीमेंट सूचकांक दिसंबर में 2.1 प्रतिशत अंक ऊपर आया। रोजगार की स्थिति, व्यक्तिगत

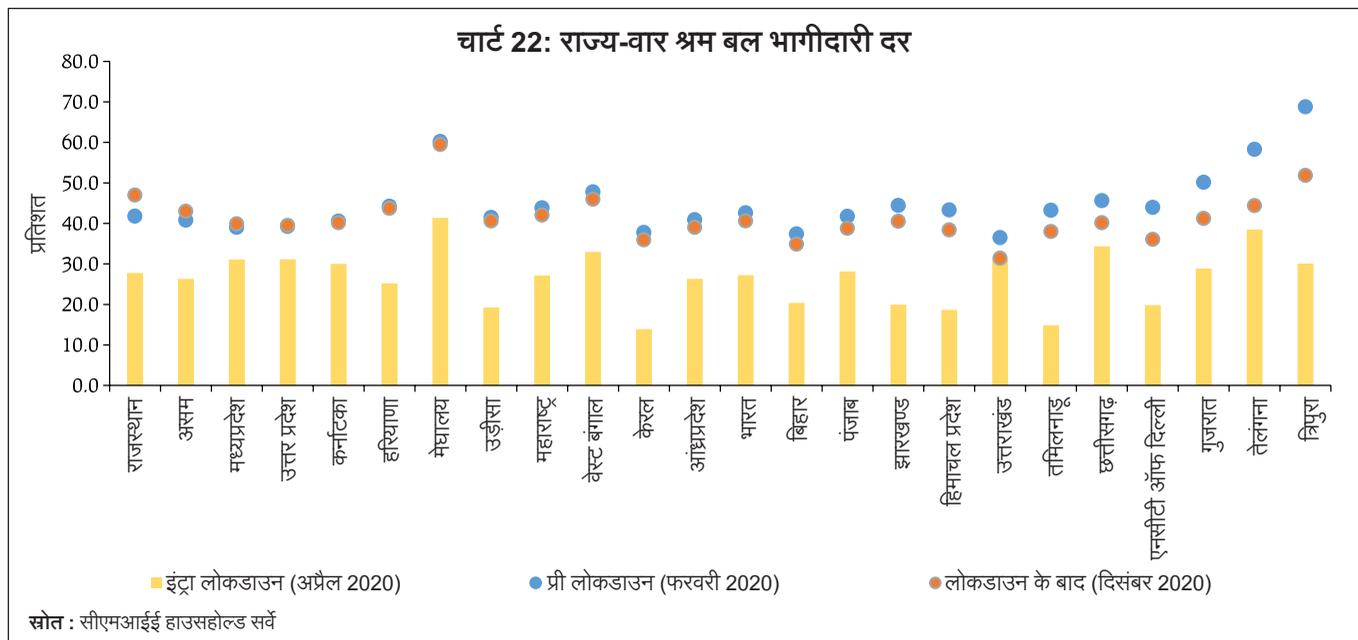




मूल्यवर्धित वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए एक बड़े रुझान के पहले, स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रय को वरीयता मिलने की उम्मीद है। बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स से संबन्धित लोगों और किराने की दुकानों के बीच गठजोड़ के विस्तार की उम्मीद है। उपभोक्ताओं का रुझान आवास की ओर भी हुआ है। आवासीय क्षेत्र की बिक्री में ति. 3: 2020-21 में तेज वृद्धि के साथ आवास क्षेत्र के मुड़ने के संकेत हैं - पूर्ववर्ती तिमाही का स्तर लगभग दोगुना - अनुकूल ब्याज दरों से समर्थित, अभी भी आवास की कीमतें अवरुद्ध हैं, डेवलपर्स द्वारा सूची को निपटाने के लिए अधिक छूट और कुछ राज्यों द्वारा स्टाम्प शुल्क में कमी (चार्ट 21)। उपभोक्ता खर्च का फिर से आरंभ होना, भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) बाजार में से भी स्पष्ट है, जिसका विस्तार 17.0 प्रतिशत⁴ है।

वित्त, निवेश के माहौल और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में विश्वास के संबंध में सुधार दर्ज किया गया। इस बात की पुष्टि उन और ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट द्वारा की गई है कि उपभोक्ता विश्वास जनवरी 2021 से सुधरेगा, जुलाई में चरम पर रहेगा और अगले त्योहारों के समय से पहले सितंबर तक जारी रहेगा। क्रय व्यवहार से डिजिटल और ओमनी- चैनल की बिक्री के माध्यम से

श्रम बाजार की स्थिति भी पैरी पासू सुधार कर रही है, जिसमें स्थान और समय के साथ रोजगार में क्रमिक सुधार हुआ है, जैसा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण द्वारा इंगित किया गया है। अप्रैल 2020 (चार्ट 22) में 35.57 के निम्न स्तर से दिसंबर में श्रम बल की भागीदारी दर बढ़कर 40.06 हो गई। अंतर-राज्य प्रवास

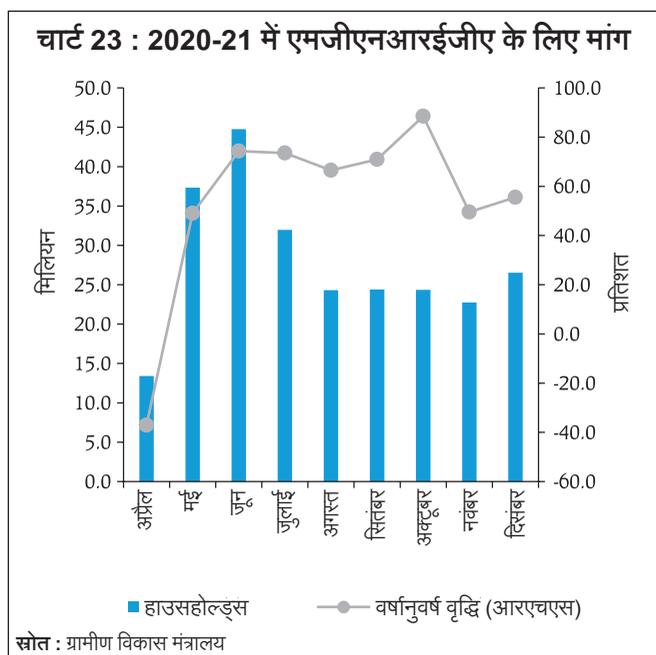


⁴ <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/faster-moving-consumer-goods-sales-up-17-in-q3/articleshow/80124785.cms>

प्रतिबंधों के क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने के साथ, राज्यों में श्रम बल भागीदारी दर दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और त्रिपुरा के को छोड़कर पूर्व-महामारी स्तर तक बढ़ गई है। राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने तेजी से सुधार दर्शाया है जिसमें दिसंबर में दर्ज की गई श्रम बल की भागीदारी पूर्व-लॉकडाउन अवधि (चार्ट 23) में देखी गई भागीदारी की तुलना में अधिक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत, लगभग 26.5 मिलियन परिवारों ने दिसंबर में रोजगार की मांग की जो पूर्ववर्ती महीने की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक था और एक साल पहले की तुलना में 55.5 प्रतिशत से अधिक था। दिसंबर के अंत तक, बजट की राशि का 130 प्रतिशत खर्च कर दिया गया था।

यह संभावना है कि आने वाले महीनों में रोजगार की स्थिति और भी अधिक उज्ज्वल होगी। स्टाफिंग समाधान प्रदाता टीमलीज के अनुसार, 2021 में विभिन्न कौशल सेट के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फर्मों द्वारा लोगों को काम पर रखने के संबंध में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बेहतर विकास जो बहाली की संभावनाओं में सुधार करता है, वह सरकारी खर्चों की अच्छी बहाली है। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय की



वृद्धि देने वाली भूमिका ऐसे समय में अमूल्य है जब महामारी के कारण उत्पन्न मेटास्टेसिस के अंतर्गत जीडीपी के अन्य सभी घटकों में अत्यधिक कमी आई हो। निकट-अवधि के दृष्टिकोण के लिए इस गतिविधि की महत्ता को पूरी तरह से समझना कठिन है इस वर्ष दिसंबर 2020 के बुलेटिन में छापे एक आर्टिकल जिसका शीर्षक था 'गवर्नमेंट फाइनेंस 2020-21: एक अर्धवार्षिक समीक्षा '(आरबीआई 2020) जिसमें अंतर्निहित डायनामिक्स पहली बार उजागर हुईं जो संयोगवश, आईएमएफ के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) के साथ भारत के अनुपालन को पूरा करती है।

इस लेख के नवंबर 2020 के संस्करण ने विवरण प्रदान किया और केंद्र द्वारा दिए गए प्रोत्साहन में 'प्रणाली' को निर्धारित किया। इससे पहले, स्टेट फ़ाइनेंस (आरबीआई, 2020) पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कैसे राज्यों ने कई असफलताओं के साथ महामारी के खिलाफ रक्षा में मोर्चेबंदी करने वालेयोद्धाओं के रूप में कमान संभाली, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी सफलताएँ भी हासिल कीं जिन्होंने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस लॉग क्रोनिकल के नीचे, वास्तविकता यह है कि महामारी ने सरकारी वित्त पर एक 'कैची का प्रभाव' डाला है। एक ओर, इसने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय समर्थन के लिए खर्च को बढ़ाया, जो 2020-21 के लिए बजट तैयार करने के समय पूरी तरह से अप्रत्याशित था। दूसरी ओर, राजस्व में संकुचन था क्योंकि अर्थव्यवस्था में गतिविधि लॉकडाउन और अन्य नियंत्रण उपायों के कारण कैटेटोनिक निकासी में चली गई थी। परिणामस्वरूप, सामान्य सरकारी सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) एच1: 2020-21 में 14.5 प्रतिशत तक बढ़ गया, ति. 1 में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई जिसके परिणामस्वरूप व्यय के युक्तिकरण और प्रत्यावर्तन के रूप में ति.2 इसके में समेकन की आवश्यकता पड़ी (चार्ट 24)। आगे बढ़ते हुए, ये दो सकारात्मक विशेषताएं एच 2 में वित्तीय परिदृश्य को आकार देने जा रही हैं। सबसे पहले, सामान्य सरकारी जीएफडी-जीडीपी अनुपात 10.4 प्रतिशत से कम होने की संभावना है (50 प्रतिशत कोन्फ़ीडेंस बैंड के भीतर 9.7-10.9 प्रतिशत)। यह विकास राजस्व द्वारा संचालित होगी क्योंकि एच 2 द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आ गए होंगे और प्राप्ति सकारात्मक हो चुकी होगी। दूसरा, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता भी एच 2 में बेहतर होने की संभावना है क्योंकि, आत्मा निर्भर के अंतर्गत दिए जाने वाले

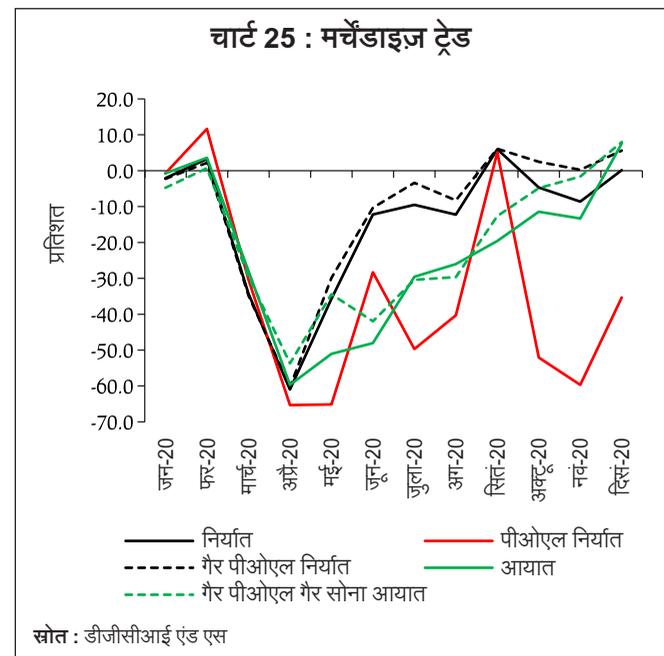
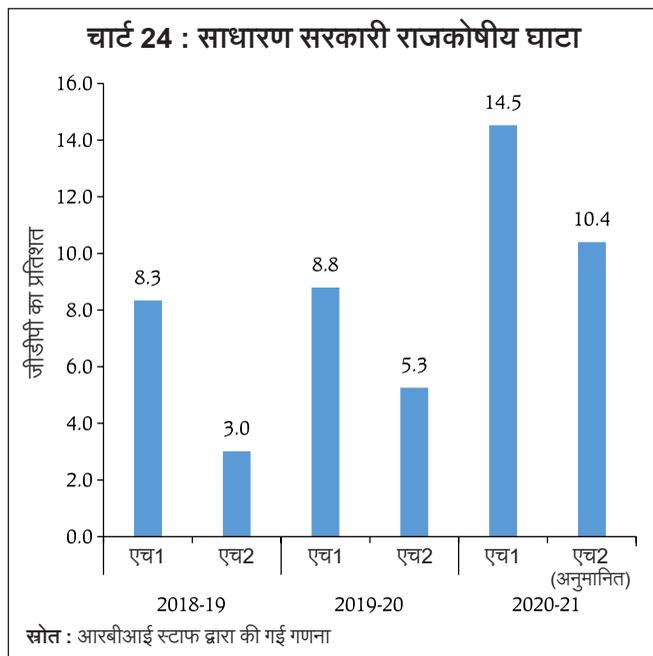
निवेश उन्मुख प्रोत्साहन के एक बड़े हिस्से 2.0 और 3.0 (क्रमशः अक्टूबर और नवंबर 2020 में घोषणा की गई) का इसी अवधि में फलीभूत होने की उम्मीद है। यह नवंबर 2020 में कैपेक्स के मासिक डेटा में पहले से ही स्पष्ट है ; हालाँकि, केंद्र और राज्यों दोनों को राजकोषीय चिंताओं के लिए बड़े पैमाने पर खर्च में कटौती का विरोध करना चाहिए।

बाहरी मांग की ओर रुख करें तो भारत का माल निर्यात कोविड -19 के पूर्व के स्तर तक पहुँच गया है और दिसंबर 2020 में इसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। गैर-तेल निर्यात वास्तव में 5.6 प्रतिशत तक बढ़ा है, जो लगातार चौथे महीने में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अधिक उल्लेखनीय माल के आयात में हुआ सुधार था, जो नौ महीने के संकुचन के बाद दिसंबर 2020 में 7.6 प्रतिशत तक पलट गया है। यह सुधार सोने, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वनस्पति तेलों द्वारा किया गया था। मोती और कीमती पत्थरों, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वस्त्रों के बढ़ते आयात घरेलू गतिविधि के सुधार को दर्शाते हैं क्योंकि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं में मध्यवर्ती माल की प्रकृति के हैं। यह निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से विकसित करता है। तेल आयात के मामले में भी, संकुचन की दर में गिरावट देखी गई,

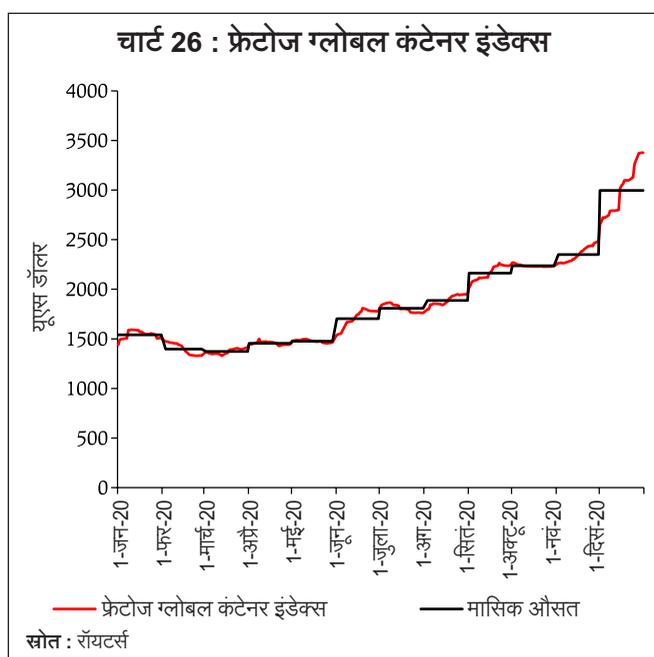
तेल के आयात में दिसंबर में केवल 10.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि यह नवंबर में 43.4 प्रतिशत की तेज गिरावट थी। आयात में बेहतर वृद्धि के साथ, व्यापार घाटा सत्रह महीनों में सबसे अधिक, दिसंबर (चार्ट 25) में यूएस \$ 15.4 बिलियन से अधिक का हो गया।

गैर-तेल निर्यात में तेजी से सुधार के लिए ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि वस्तुओं और लौह अयस्क के शिपमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें से सभी ने महामारी के समय में लचीलापन और विश्व व्यापार में बड़े पैमाने पर संकुचन को प्रदर्शित किया है। जैसे ही दुनिया भर में टीकाकरण की गति बढ़ती है, वैसे ही दुनिया में वैक्सीन निर्माण में सबसे बड़ी क्षमता के मामले में भारतीय फार्मा फर्मों का फायदा होगा - भारत पहले से ही वैश्विक स्तर पर बेचे जाने वाले टीकों का 60 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा, बल्क ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और उम्मीद की जा रही है कि इससे फार्मास्यूटिकल और मेडिकल एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, जबकि कच्चे माल और इंटरमीडिएट के मामले में भारत को कमजोर पड़ने की आशंका कम होगी।



निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्क और कर पर छूट की योजना के तहत लाभ के विस्तार RoDTEP को 1 जनवरी, 2021 से सभी निर्यात माल के लिए प्रभावी करने के चलते भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धा के बढ़ने की उम्मीद है⁵। दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण कंटेनर आपूर्ति की कमी, शिपिंग लाइनों की घटी हुई क्षमता, लॉकडाउन के दौरान बंदरगाहों पर फंसे खाली कंटेनर, बंदरगाह जनशक्ति में कमी के कारण कार्गो हैंडलिंग की गति में कमी और परिणामस्वरूप बंदरगाहों में अत्यधिक सामान का होना भारत के निर्यात की संभावनाओं के लिए जोखिम का कारण है। विशेष रूप से भारतीय निर्यात के लिए, कोलंबो बंदरगाह पर भारी भीड़ द्वारा स्थिति बिगड़ गई थी, जो भारतीय कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कोलंबो से कार्गो यातायात का एक बड़ा हिस्सा कोच्चि बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया है। इसने नवंबर-दिसंबर 2020 (चार्ट 26) के दौरान बढ़ते ग्लोबल कंटेनर फ्रेट इंडेक्स में दर्शाए गए अनुसार माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की है।

भारत का चालू खाता जुलाई-सितंबर 2020 (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) में लगातार तीसरी तिमाही के लिए अधिशेष में रहा,



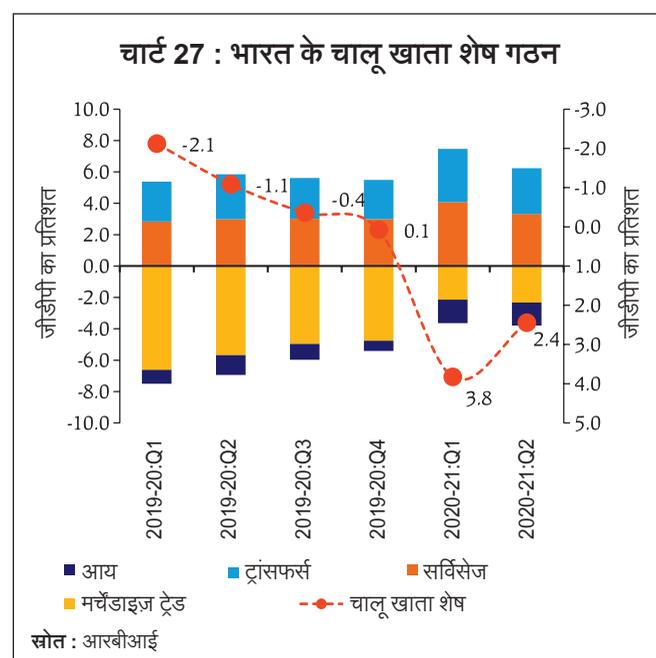
⁵ आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को उनके द्वारा केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संदत शुल्कों / करों जिन्हें अब तक रीबेट नहीं दिया गया था /रीफंड नहीं किया गया था।

हालांकि यह घरेलू मांग (चार्ट 27) के फिर से शुरू होने के साथ कम हो गया। जबकि भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों में अधिशेषों का सह-अस्तित्व विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रदान किए गए बफर को मजबूत करता है, भारत सुस्त प्रतिरोधक क्षमता के साथ संतुष्ट है। सिल्वर लाइनिंग यह है कि चालू खाते का अधिशेष ति.2 में हटना शुरू हो गया है और एच 2: 2020-21 में इसके और कम होने की संभावना है।

सकल आपूर्ति

कृषि में लचीलापन और विनिर्माण गतिविधि में पुनरुत्थान के आधार पर दिसंबर 2020 तक सकल आपूर्ति की स्थिति मजबूत हुई। सेवा क्षेत्र की गतिविधि भी सुधरती हुई प्रतीत होती है, हालांकि संपर्क-गहन सेवाएं पूर्व-कोविड स्तरों के नीचे बनी हुई हैं।

महामारी से कृषि सुरक्षित है। प्रमुख फसलों की बुवाई सामान्य स्तर से अधिक हो गई है। 15 जनवरी, 2021 तक रबी की बुआई का रकबा 651.9 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक था, और पूरे सीजन के सामान्य रकबे (तालिका 3) को पार कर गया। जलाशय का स्तर 14 जनवरी को पूर्ण क्षमता के 68 प्रतिशत के बराबर था, जो कि औसतन 56 प्रतिशत रहता है; यह रबी



तालिका 3: अखिल भारतीय फसल स्थिति - रबी (2020-21)
15 जनवरी, 2021 को

(लाख हेक्टेयर में क्षेत्रफल)

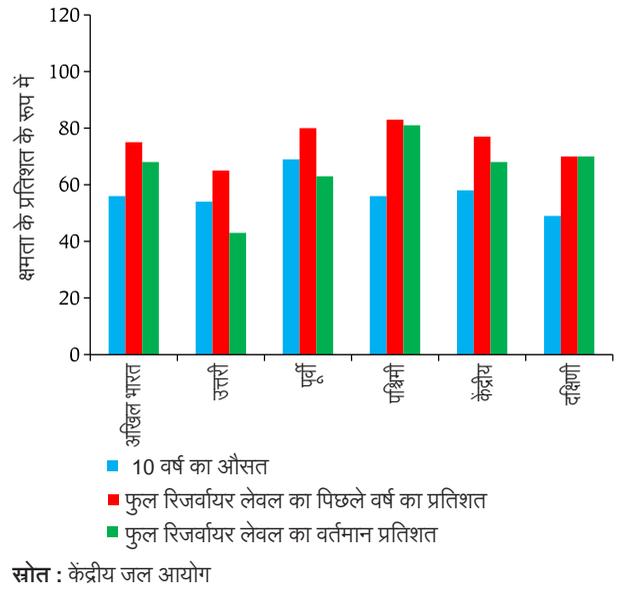
फसल का नाम	प्रतिशत भिन्नता		तिथि के अनुसार बुवाई करें		प्रतिशत भिन्नता	
	पूरा सीजन	आज की तारीख में	इस वर्ष (2021)	पिछले साल (2020)	आज की तारीख में सामान्य से अधिक	पिछले साल से अधिक
1. गेहूँ	303.3	306.8	337.1	330.6	9.9	2.0
2. चावल	41.8	19.7	21.0	20.0	6.8	5.0
3. मोटे अनाज	57.1	52.9	49.1	53.5	-7.2	-8.2
क. ज्वार	33.4	30.3	26.5	29.4	-12.7	-10.0
ख. जौ	6.4	7.4	6.8	7.6	-7.5	-10.5
ग. मक्का	17.4	14.5	14.8	15.1	4.1	-4.9
4. कुल दालें	144.9	152.4	162.1	158.8	6.4	2.1
क. ग्राम	92.8	98.9	109.1	105.5	10.4	3.5
ख. मसूर	14.2	16.3	16.4	16.0	1.1	2.5
ग. मटर	8.8	10.4	10.6	10.9	1.9	-2.3
घ. कुल्थी (हॉर्स ग्राम)	2.2	4.5	3.8	5.1	-15.8	-26.0
ङ. उड़द	8.9	7.6	7.6	7.1	-0.2	6.5
च. मूंग	9.9	5.4	5.2	5.5	-3.5	-4.2
छ. लेंथिरस	4.0	3.5	3.1	3.1	-11.7	0.0
I. कुल खाद्यान्न (1+2+3+4)	547.1	531.8	569.4	562.9	7.1	1.1
5. तिलहन	73.2	79.2	82.6	79.0	4.3	4.6
क. रेपसीड एंड मस्टर्ड	59.4	79.2	73.2	68.6	-7.5	6.7
ख. मूंगफली	7.3	4.6	4.3	4.5	-6.3	-5.1
ग. सूरजमुखी	2.4	1.6	1.0	1.0	-41.4	-1.9
घ. तिल	0.0	0.5	0.4	0.5	-20.2	-22.3
ङ. कुसुम	1.2	0.8	0.6	0.6	-25.5	-6.4
च. अलसी का बीज	2.7	3.5	2.8	3.3	-18.4	-14.3
सभी फसलें (1+2+3+4+5)	620.3	610.9	651.9	641.9	6.7	1.6

नोट: क्षेत्र के आंकड़े राज्य कृषि विभागों के आंखों देखे आकलन के अनुसार हैं। सामान्य क्षेत्र: 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान औसत क्षेत्र दिनांक के अनुसार सामान्य क्षेत्र: 2015-16 से 2019-20 की इसी अवधि के दौरान औसत क्षेत्र।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

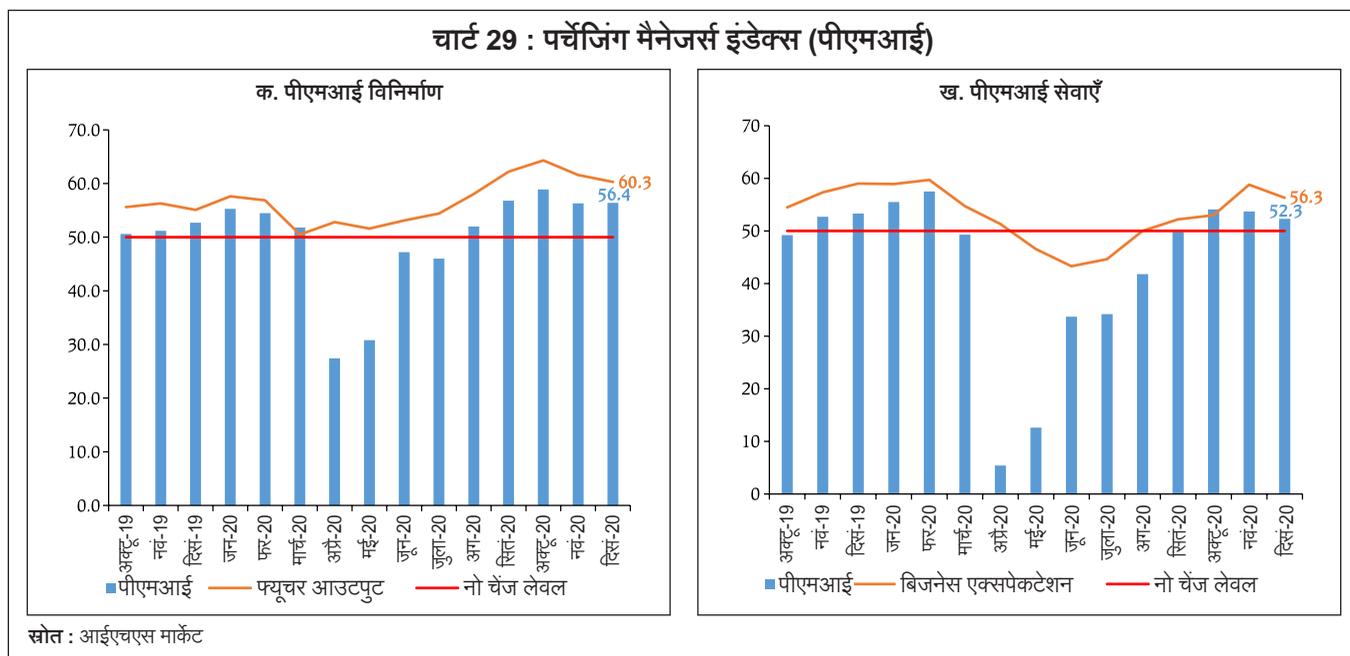
मौसम (चार्ट 28) के लिए एक बल को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। गेहूँ - प्राथमिक रबी स्टेपल - ने बुवाई में वृद्धि दर्ज की है (2.0 प्रतिशत), मुख्य रूप से प्रमुख उत्पादक राज्यों में अधिक बुवाई के कारण, विशेष रूप से हरियाणा (1.2 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (12.7 प्रतिशत)। दलहन और तिलहन ने भी रकबे में शानदार बदलाव दर्ज किया है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के साथ, 51.3 मिलियन टन खरीफ चावल की खरीद एक साल

चार्ट 28 : रिजर्वार लेवल



पहले की तुलना में 26.2 प्रतिशत अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2021 तक अनाज (चावल और गेहूँ) बफर स्टॉक 3.7 बढ़ गया।

हालांकि औद्योगिक उत्पादन अस्थिर बना हुआ है, अक्टूबर 2020 में 4.2 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि के बाद नवंबर 2020 में 1.9 प्रतिशत के बाद औद्योगिक गतिविधि आखिरकार बदल रही है। हेडलाइन क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण दिसंबर 2020 में बढ़कर 56.4 हो गया, जो नवंबर के 56.3 (चार्ट 29) से थोड़ा सा ही अधिक है। नए ऑर्डर आदेश और आउटपुट दोनों दृढ़ता से बढ़ते रहे। भविष्य के उत्पादन सूचकांक में बाजार की स्थितियों में सुधार की उम्मीद पर 60.3 तक विस्तार किया गया, हालांकि मुद्रास्फीति के दबावों पर चिंताओं के कारण आत्मविश्वास में कमी आई। औद्योगिक गतिविधि में क्रमिक सुधार के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड ने ति.3 में कोयला उत्पादन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यात्री कार वाहनों की बिक्री के संबंध में, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) में से अधिकांश ने दिसंबर में दोहरे अंक की वृद्धि देखी, जिससे वर्ष की समाप्ति सकारात्मक रही, क्योंकि उन्होंने अपनी इनवेंटरीज़ को फिर से भर लिया। सड़क और परिवहन मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2020 में पूरे भारत में 1.8 मिलियन से



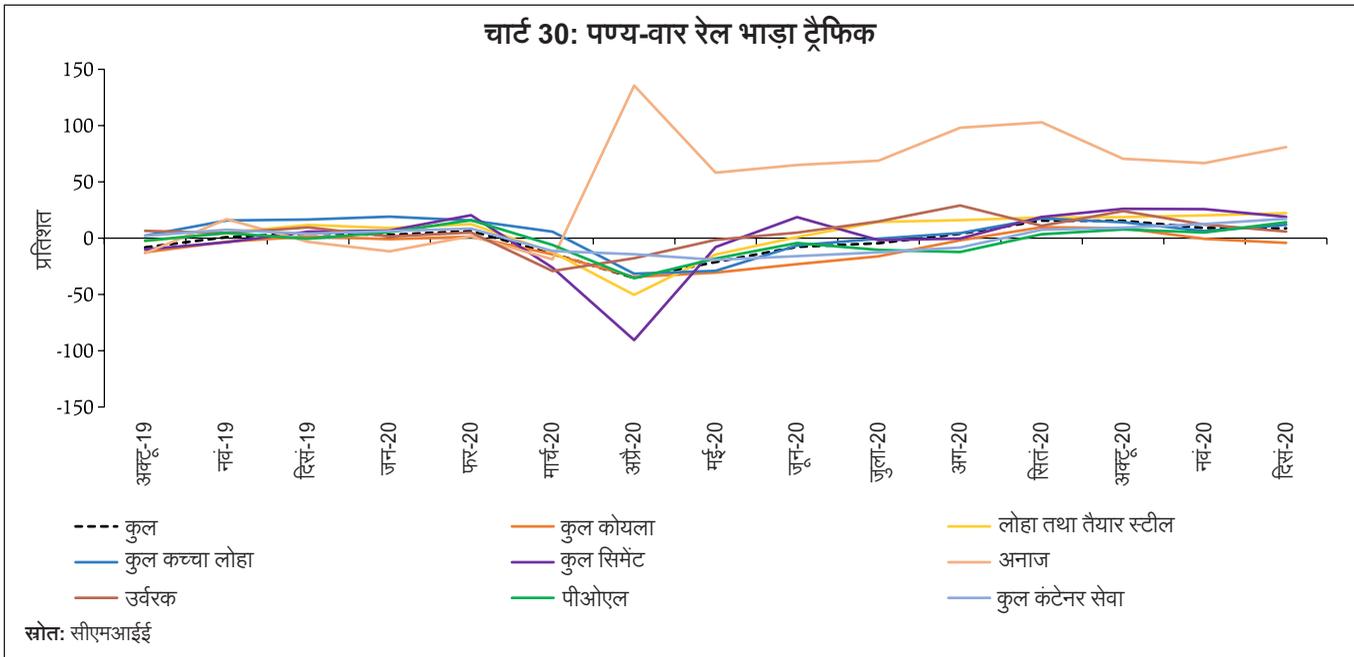
अधिक वाहनों का पंजीकरण किया गया था, जो अप्रैल के बाद से अब तक का सबसे अधिक है – महामारी की अवधि में पहली बार 10.3 प्रतिशत की वृद्धि। इस गतिविधि में तेजी मुख्य रूप से गैर-परिवहन वाहनों के क्षेत्र में थी। मिनी-ट्रकों, पिक-अप वैन और अन्य हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है क्योंकि अधिक भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ग्राहक तक वितरण करने संबंधी लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता बढ़ गई है।

सेवा क्षेत्र में, एक स्थिर सुधार हो रहा है। सेवाओं की पीएमआई लगातार तीसरे महीने में बढ़कर दिसंबर में 52.3 हुई, जो नए घरेलू कार्य बढ़ने के कारण है। इस्पात की खपत - निर्माण गतिविधि के लिए एक अनुमानित संकेतक है - यह भी लगातार तीसरे महीने में बढ़ी और 5.7 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। लोडिंग और आय दोनों के मामले में रेलवे के माध्यम से परिवहन सेवाओं ने प्रभावी गति का प्रदर्शन जारी रखा। दिसंबर में 8.7 प्रतिशत की रफ्तार से माल यातायात बढ़ी, जिसकी शुरुवात अगस्त में हुई थी तथा लगातार पाँच महीने तक इसकी वृद्धि की गति का विस्तार हुआ (चार्ट 30)। कोयले के अपवाद को छोड़कर, सभी पण्य वस्तुओं की श्रेणियों में व्यापक बढ़ोतरी हुई। बंदरगाह

का भी निरंतर विस्तार जारी रहा, जिसने आठ महीने के संकुचन के बाद दिसंबर में लगातार दूसरे महीने में वृद्धि दर्ज की। संपर्क से बचने के लिए व्यक्तिगत यात्रा को प्राथमिकता मिलने के कारण, दिसंबर में लगातार पांचवें महीने के लिए यात्री वाहन बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज हुई।

मुद्रास्फीति

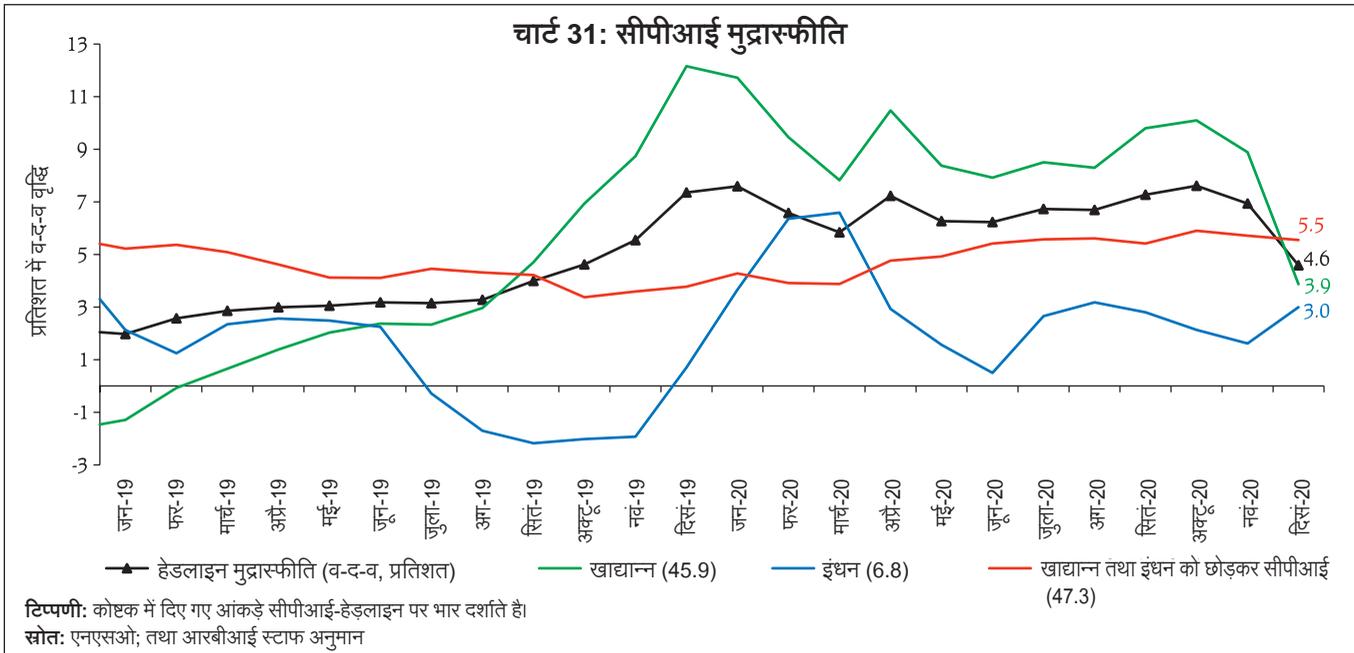
दिसंबर 2020 में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.9 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 4.6 प्रतिशत हो गई। यह मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर के 8.9 प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम होकर - दिसंबर में 3.9 प्रतिशत होने के कारण था (चार्ट 31)। सब्जियों और अनाज के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आयी। प्याज और आलू की कीमतों में हाल के महीनों में काफी वृद्धि हुई थी, जिसमें दिसंबर में तेजी से गिरावट आई। अन्य सब्जियों की कीमतों में भी मौसमी गिरावट देखी गई। एक अनुकूल प्रभाव के कारण, दिसंबर में सब्जी की कीमतों में दोहरे अंक की कमी आई। उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलें विभाग) से उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा के आधार पर, जनवरी (1-13 जनवरी, 2021) के लिए प्रमुख खाद्य कीमतों के पूर्व संकेतक सब्जियों की कीमतों में और



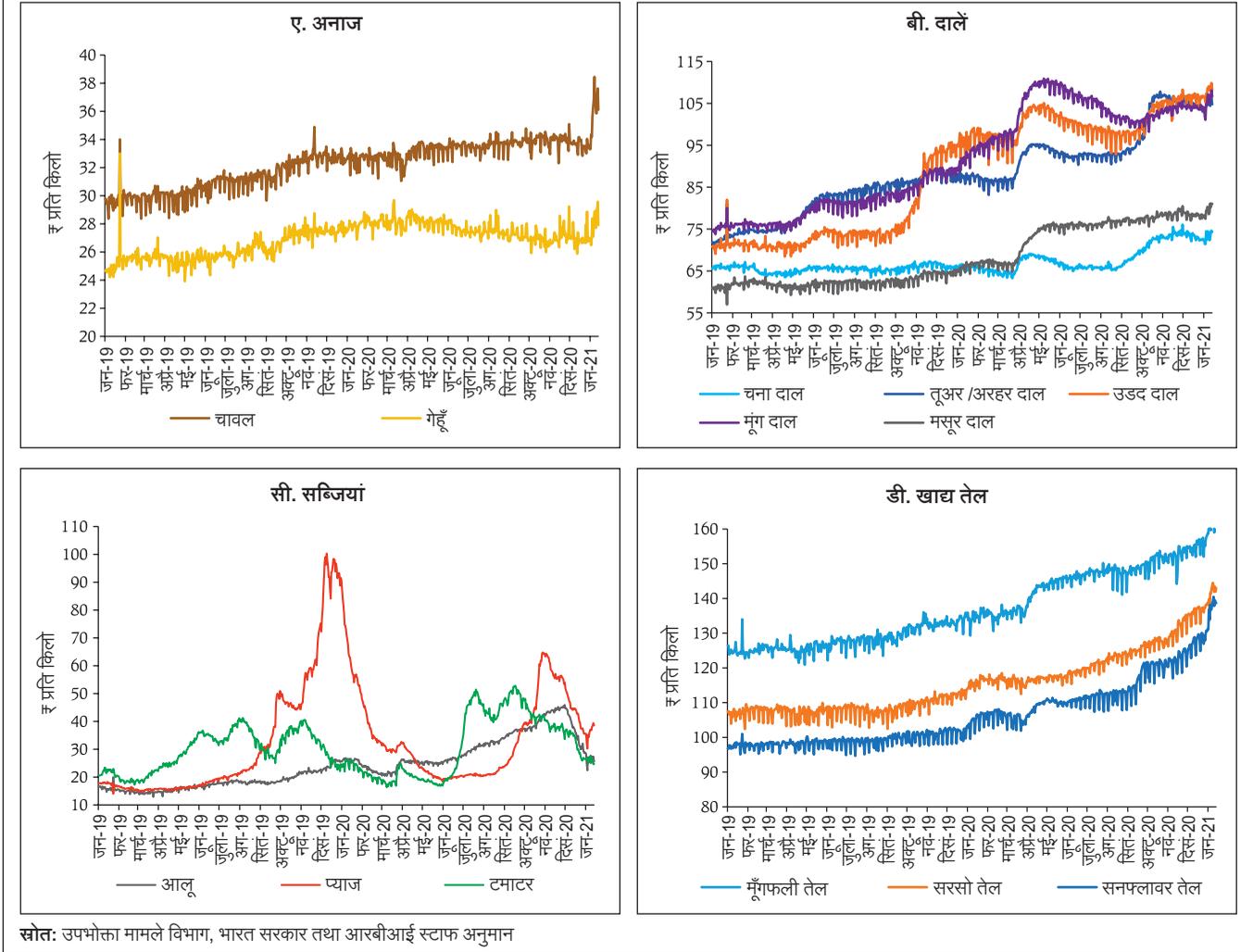
अधिक कमी दर्शाते हैं। हालांकि, खाद्य तेलों में कीमतों का दबाव जनवरी में अब तक जारी रहा है (चार्ट 32)।

भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमतें जनवरी में अब तक 53 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल (1-13 जनवरी 2021) हो गयी हैं

जो दिसंबर में 50 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। इसके परिणामस्वरूप जनवरी में अब तक घरेलू पंप कीमतों में और वृद्धि हुई है। इसके साथ, घरेलू उत्पाद शुल्क और राज्य करों में हुई अत्यधिक वृद्धि अप्रत्यावर्तित होने के कारण पंप



चार्ट 32: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें



की कीमतें ऐतिहासिक उच्च स्तर तक बढ़ रही हैं। जनवरी में घरेलू केरोसीन की कीमतें भी और बढ़ीं। एलपीजी की

कीमतों में दिसंबर में लगभग ₹100 प्रति सिलेंडर की तेज वृद्धि के बाद, जनवरी 2021 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी4)।

सारणी 4: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें (चार प्रमुख महानगरों का औसत)

मद	युनिट	घरेलू कीमतें			महीने-दर-महीने	
		जन 20	दिसं 20	जन 21	दिसं 20	जन 21
पेट्रोल	₹/लीटर	77.79	86.27	86.73 ^	2.5	0.5
डीजल	₹/लीटर	70.52	77.59	78.08 ^	3.8	0.6
केरोसीन	₹/लीटर	28.80	23.21	25.83	4.7	11.3
एलपीजी	₹/सिलेंडर	699.88	704.63*	704.63	16.5	0.0

*: 15 दिसंबर 2020 से लागू

^: 1-13 जनवरी 2021 की अवधि के लिए

टिप्पणी: चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लिए जाने वाले कीमतों का औसत।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मुख्य रूप से टेलीफोन शुल्क, शिक्षा खर्च और सोने की कीमतों में कुछ नरमी के कारण खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई नवंबर के 5.7 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर में 5.5 प्रतिशत पर रहा। दिसंबर में व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु और पान, तंबाकू तथा नशीले पदार्थों में दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति जारी रही। कुछ नरमी के बावजूद, मोटर वाहनों की कीमतों, पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और परिवहन किराए के कारण दिसंबर में परिवहन और संचार मुद्रास्फीति बढ़ गई।

सब्जियों की कीमते कम होने के कारण मुख्य रूप से सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में काफी नरमी देखी जा रही है। निकट महीनों में, जनवरी में बर्ड फ्लू के संक्रमण की घटनाओं के कारण पोल्ट्री उत्पादों की मांग में कमी आने से अंडे और पोल्ट्री, मांस और मछली की कीमतें भी कम हो सकती हैं। दूसरी ओर, सीपीआई प्रमुख घटकों पर मूल्य दबाव बने रहने की संभावना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का पीएमआई दिसंबर में निविष्टी लागत का दबाव उग्र होने की ओर इशारा करते हैं। यह ईंधन की लागत, औद्योगिक धातु की कीमतों, खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि और लॉकडाउन स्थिति के बाद में व्यापार की बढ़ती लागत के कारण है। ऐसी स्थिति में जहां मांग सामान्य हो रही है और कंपनियों को कीमते निर्धारित करने की शक्ति मिल रही हैं, बढ़ती निविष्टी लागत के कारण उत्पादन कीमतें बढ़ने का खतरा है।

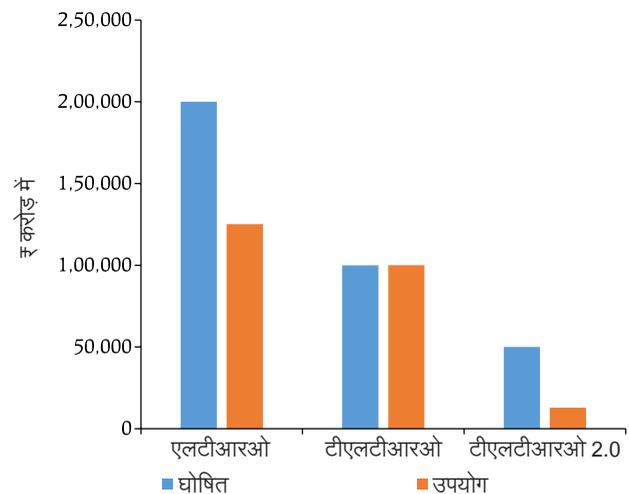
IV. वित्तीय स्थितियां

रिजर्व बैंक अपने बाजार परिचालनों के माध्यम से आसान मौद्रिक और ऋण स्थितियों के रूप में बहाली के लिए पोषक अनुरूप वित्तीय स्थितियां विकसित करना सुनिश्चित कर रहा है। महीने के उत्तरार्ध में बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर प्रवाह के बावजूद दिसंबर 2020 तक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषित राशि बढ़कर ₹5,90,822 करोड़ हो गयी। एलएएफ के तहत ओवरनाईट रिवर्स रेपो के माध्यम से अतिरिक्त चलनिधि को हटाया गया, जो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़कर ₹7,37,314 करोड़ हो गया। ऑन टैप टारगेटेड लॉग टर्म रेपो परिचालन

(टीएलटीआरओ) योजना ⁶ के तहत केंद्रीय बैंक का चलनिधि और केंद्र सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 (ईसीएलजीएस 2.0) का बैंकों द्वारा लाभ उठाया जा सके इसलिए, रिजर्व बैंक ने 21 दिसंबर 2020 को योजना के तहत घोषित पाँच क्षेत्रों के अलावा कामत समिति द्वारा दिए गए सभी दबावग्रस्त क्षेत्रों को 4 दिसंबर 2020 को ऑन टैप टीएलटीआरओ के दायरे का विस्तार किया गया। बैंक रिजर्व बैंक से ऑन टैप टीएलटीआरओ पर धन प्राप्त कर सकते हैं और दबावग्रस्त क्षेत्रों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए सीएलजीएस 2.0 के तहत गारंटी मांग सकते हैं (चार्ट 33)।

माह के दौरान 23 दिसंबर 2020 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में खुले बाजार का परिचालन (ओएमओ) आयोजित किया गया था, जिसकी राशि ₹10,000 करोड़ थी, जिससे 22 अक्टूबर 2020 से एसडीएल में ओएमओ की कुल संख्या तीन हुई। टर्म प्रीमिया पर नियंत्रण के लिए 17 और 30 दिसंबर को दो विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) भी किए गए थे।

चार्ट 33: एलटीआरओ और टीएलटीआरओ का उपयोग

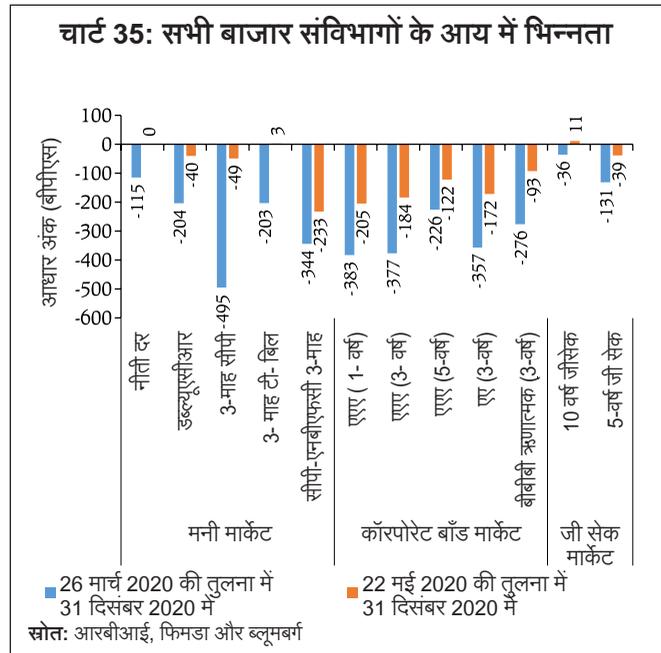
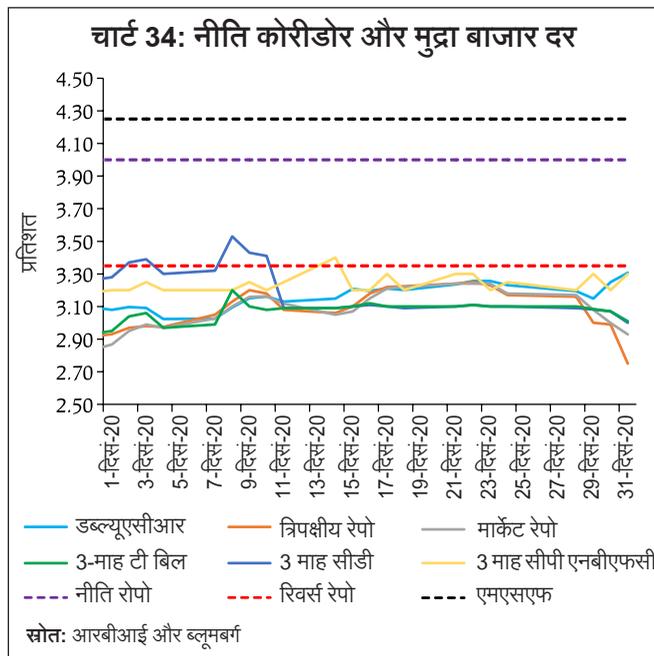


टिप्पणी: बैंकों ने एलटीआरओ टीएलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ 2.0 के अंतर्गत प्राप्त राशि का क्रमशः 98.8 प्रतिशत, 32.4 प्रतिशत तथा 38.1 प्रतिशत राशि चुकायी है।
स्रोत: आरबीआई।

⁶ इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि, कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, और विशिष्ट क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार उनके निवेश के बकाया स्तर से अधिक निवेश किया जाना चाहिए। योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग इन क्षेत्रों को बैंक ऋणों और अग्रिम देने के लिए भी किया जा सकता है।

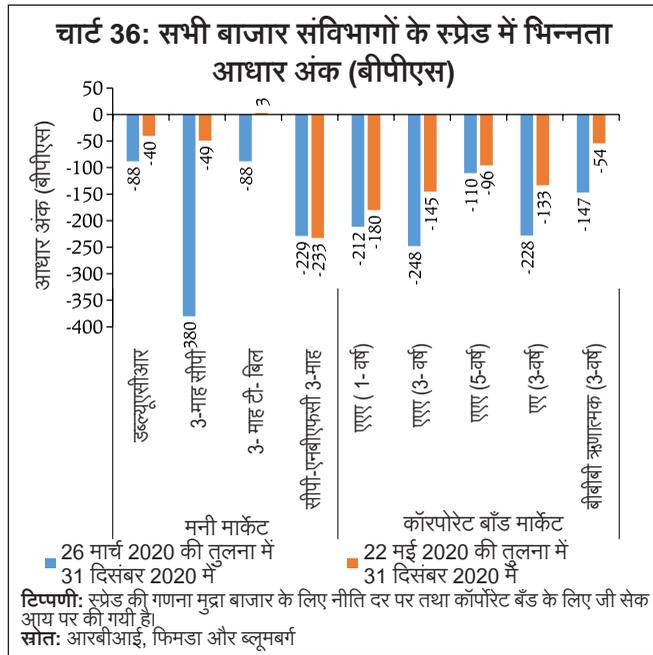
अक्टूबर 2020 के मध्य से पूरे स्पेक्ट्रम की विशेषता वाले उप-एलएफ स्तरों से रिवर्स रेपो दर के करीब बढ़ते हुए, अग्रिम कर बहिर्गमन के कारण मुद्रा बाजार की दरें थोड़ीसी बढ़ी। संपार्श्विक त्रिपक्षीय रेपो दर और बाजार रेपो दर के स्प्रेड की तुलना में भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) नवंबर में (-) 32 आधार अंक (बीपीएस) और (-) 29 बीपीएस से कम होकर दिसंबर 2020 में (-) 7 बीपीएस हो गया। यहां तक कि जमा प्रमाण पत्र (सीडी), 91-दिन के ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) की दरें ओवरनाईट दरों के करीब चली गईं, जबकि वे रिवर्स रेपो दर से नीचे कारोबार करते रहे (चार्ट 34)।

वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में, काफी हद तक स्प्रेड संकुचित हो गया, जो चलनिधि उपायों, विनियामक छूट और भावी मार्गदर्शन के प्रभाव को दर्शाता है। 22 मई और 31 दिसंबर 2020 से 1 वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्षीय एए-रेटेड स्पेक्ट्रम के कॉर्पोरेट बॉन्ड के आय में क्रमशः 205 बीपीएस, 184 बीपीएस और 122 बीपीएस की गिरावट हुई है (चार्ट 35)। यहां तक कि 3-वर्षीय बीबीबी- (बीबीबी माइनस)-रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड - सबसे कम रेटेड निवेश ग्रेड बॉन्ड की आय में - 93 बीपीएस की गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि बिना रेटिंग असर के चलनिधि दबाव एक समान रूप में कम हुआ है। परिणामस्वरूप, अवधि के दौरान क्रमशः 1 वर्ष, 3-वर्ष, 5-वर्ष एए और 3-वर्षीय बीबीबी-



रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 180 बीपीएस, 145 बीपीएस, 96 बीपीएस और 54 बीपीएस की गिरावट आई (चार्ट 36)। पुराने 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.77 जीएस 2030) की आय फिसलकर 31 दिसंबर 2020 को 5.90 प्रतिशत पर बंद हुई, जबकि नए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.85 जीएस 2030) की आय 31 दिसंबर 2020 को लगभग 5.87 प्रतिशत पर बंद हुई। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के खुलने से और गतिविधि सामान्य होने के साथ, मांग की स्थिति में सुधार, सस्ती दरें और पर्याप्त चलनिधि के कारण वित्तीय से स्थावर क्षेत्र तक संसाधनों का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।

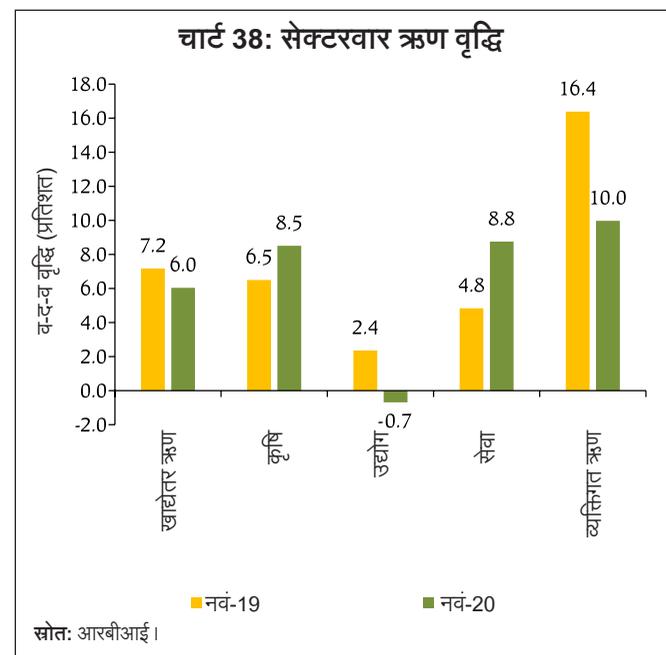
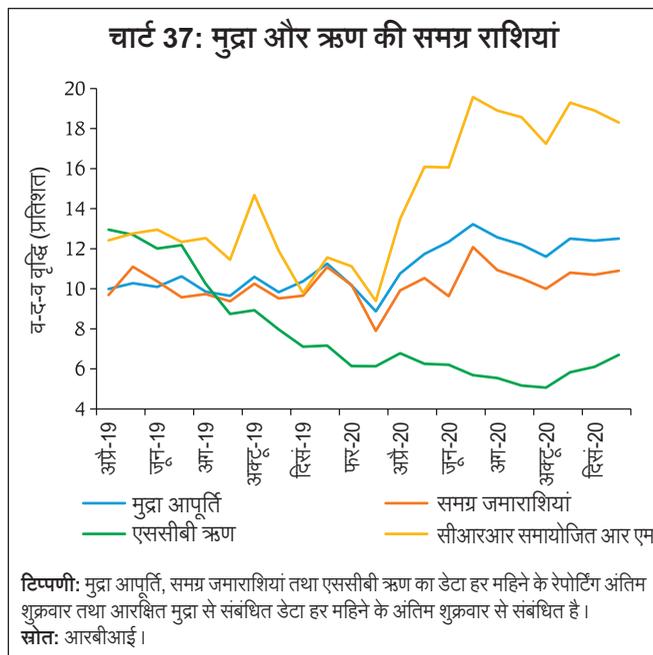
चलनिधि संबंधी व्यापक उपाय सहज मौद्रिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 8 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष 18.3 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 11.3 प्रतिशत) हुई, संसाधनों को संचालनगत मुद्रा (सीआईसी) में चल रही वृद्धि से और स्रोत को निवल विदेशी आस्ति (एनएफए) से बल मिला (चार्ट 37)। 1 जनवरी 2021 की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 10.1 प्रतिशत) हुई, जिसे 10.9 प्रतिशत से बढ़ती समग्र



शेयरों में निवेश पिछले साल की ₹10,524 करोड़ की गिरावट की तुलना में वृद्धिशील आधार पर वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक (1 जनवरी तक) ₹434 करोड़ था। अप्रैल से 1 जनवरी 2021 तक बैंकों ने वाणिज्यिक क्षेत्र को संचयी आधार पर ₹2,93,007 करोड़ का ऋण दिया है- पिछले वर्ष की तुलना में 31.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान निधि के समग्र प्रवाह में बैंक ऋण 29.8 प्रतिशत से बढ़कर 34.1 प्रतिशत हो गया। नवंबर 2020 में कृषि और सेवा क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र को ऋण संकुचित हुआ (चार्ट 38)। व्यक्तिगत वाहन ऋण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत ऋण में मंदी आई। सेवा क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण तेजी से बढ़े। जबकि उद्योग के लिए समग्र ऋण वृद्धि में गिरावट आई थी, मध्यम उद्योग को ऋण में वृद्धि हुई और इन क्षेत्रों के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के चलते सूक्ष्म और लघु उद्यम संकुचन से बाहर आए।

जमाराशि (एक वर्ष पहले 9.8 प्रतिशत) से बल मिला। पांच महीने के अंतराल के बाद, बहाली के सकारात्मक संकेतों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण 6 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत हो गया (एक वर्ष पहले 7.5 प्रतिशत)। एससीबी का वाणिज्यिक पत्र, बॉन्ड, डिबेंचर और कॉर्पोरेट निकायों के

ऋण बाजार में अतिरिक्त चलनिधि स्थिति से ब्याज दरें कम हो गयीं। मार्च से दिसंबर 2020 तक की अवधि में माध्यम अवधि जमा दर (एमटीडीआर) में 146 बीपीएस की गिरावट आई है, एक वर्ष की परिपक्वता के छोटे अवधि की जमाराशियों में गिरावट



सारणी 5: बैंकों की जमा और उधार दरों में रेपो रेट का ट्रांसमिशन

(आधार अंक)

अवधि	रेपो रेट	मीयादी जमा दरें		उधार दरें		
		मीडियन टर्म डिपॉजिट रेट	डब्ल्यूएडीटीडीआर	1-वर्ष मीडियन एमसीएलआर	डब्ल्यूएलआर बकाया रूपया ऋण	डब्ल्यूएलआर नए रूपया ऋण
फरवरी 19 - सितंबर 19	-110	-9	-7	-30	2	-40
19 अक्टूबर - दिसंबर 20*	-140	-177	-120	-115	-85	-125
20 मार्च- दिसंबर 20*	-115	-146	-81	-95	-67	-94
19 फरवरी - दिसंबर 20*		-210	-127	-145	-83	-165

*: डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा नवंबर 2020 से संबंधित है।

डब्ल्यूएलआर: वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट

डब्ल्यूएडीटीडीआर: वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट

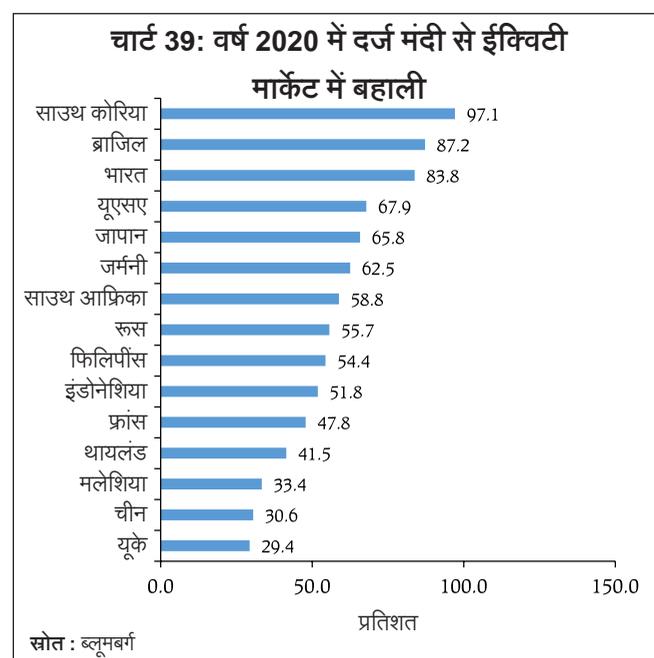
एमसीएलआर: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट

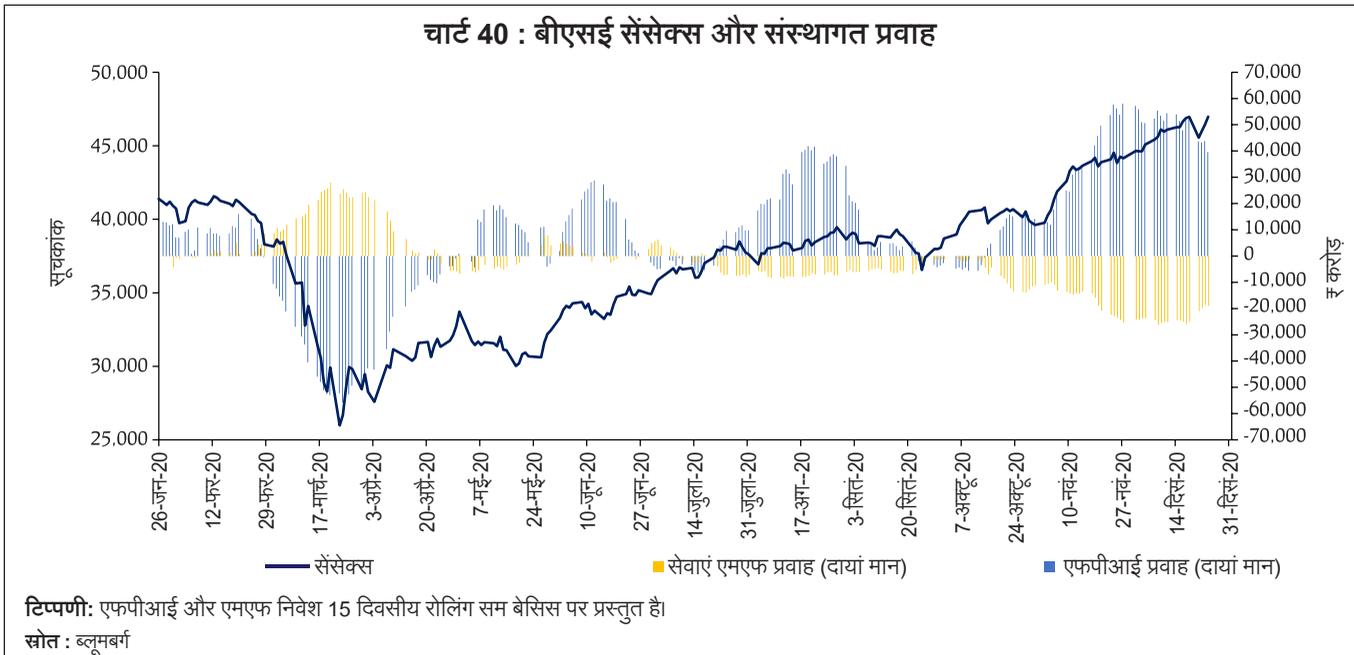
स्रोत : आरबीआई

देखी गयी है (163 बीपीएस)। जमा दरों में प्रारंभिक समायोजन, जो अन्यथा पिछड़ गया है, उधार दरों का संचरण आगे बढ़ने के संकेत देता है। इसी अवधि के दौरान, 1-वर्ष का माध्य एमसीएलआर क्रमिक रूप से कुल 95 बीपीएस से कम हुआ (सारणी 5)। जमा और उधार दरों के बीच की संचरण विषमता को संरचनात्मक अपरिवर्तनीयता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि थोक या बाजार आधारित वित्त पोषण के स्थान पर बैंकों की खुदरा जमा पर निर्भरता बढ़ रही है।

प्रतिबंधों को कम करते हुए और सामान्य गतिविधियों की बहाली के द्वारा लॉकडाउन के क्रमिक रूप से रोल-बैक के साथ, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के कारोबारी घंटे, जो पहले 7 अप्रैल 2020 से कम किए गए थे, 9 नवंबर 2020 के बाद से चरणबद्ध तरीके से बहाल किए गए। बाद में, 8 जनवरी 2021 को घोषणा की गई कि सामान्य चलनिधि प्रबंधन संचालन चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत 15 जनवरी 2021 को आयोजित परिवर्ती दर रिवर्स रेपो नीलामी से होगी। इसके साथ ही, 15 जनवरी से इस लेख को प्रकाशित करने के दौरान ₹4.4 लाख करोड़ रुपये ऑर्डर के औसत दैनिक अवशोषित चलनिधि के साथ स्थिर दर रिवर्स रेपो पूरी तरह से चालू रहा। सामान्य परिचालन की क्रमिक बहाली को कैलिब्रेट करते हुए, रिजर्व बैंक ने अनुकूल वित्तीय स्थितियों का समर्थन करने और बहाली के प्रोत्साहन के प्रयोजन से प्रणाली में पर्याप्त तरलता उपलब्ध करना सुनिश्चित किया है।

बहाली जोर पकड़ रही है यह स्पष्ट होने के कारण और अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज तथा ब्रेक्सिट व्यापार समझौते के पारित होने से सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण इक्विटी बाजार दिसंबर में अपनी तेजी में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बाजार में अतिउत्साह के कारण अधिकतर वैश्विक साधियों की तुलना में भारतीय इक्विटी में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, 31 दिसंबर 2020 को बीएसई सेंसेक्स 47,751 को छूने के साथ, 23 मार्च 2020 (25,981) के निचले स्तर से 83.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 39 और 40)।

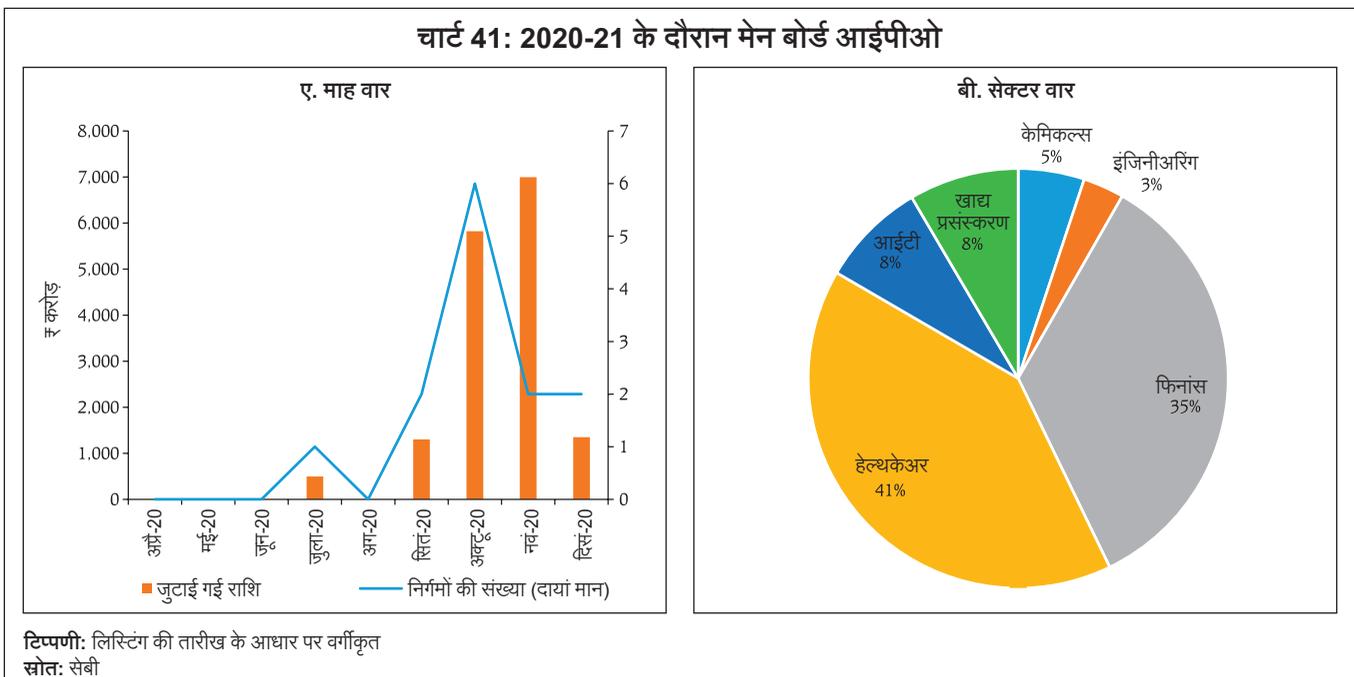


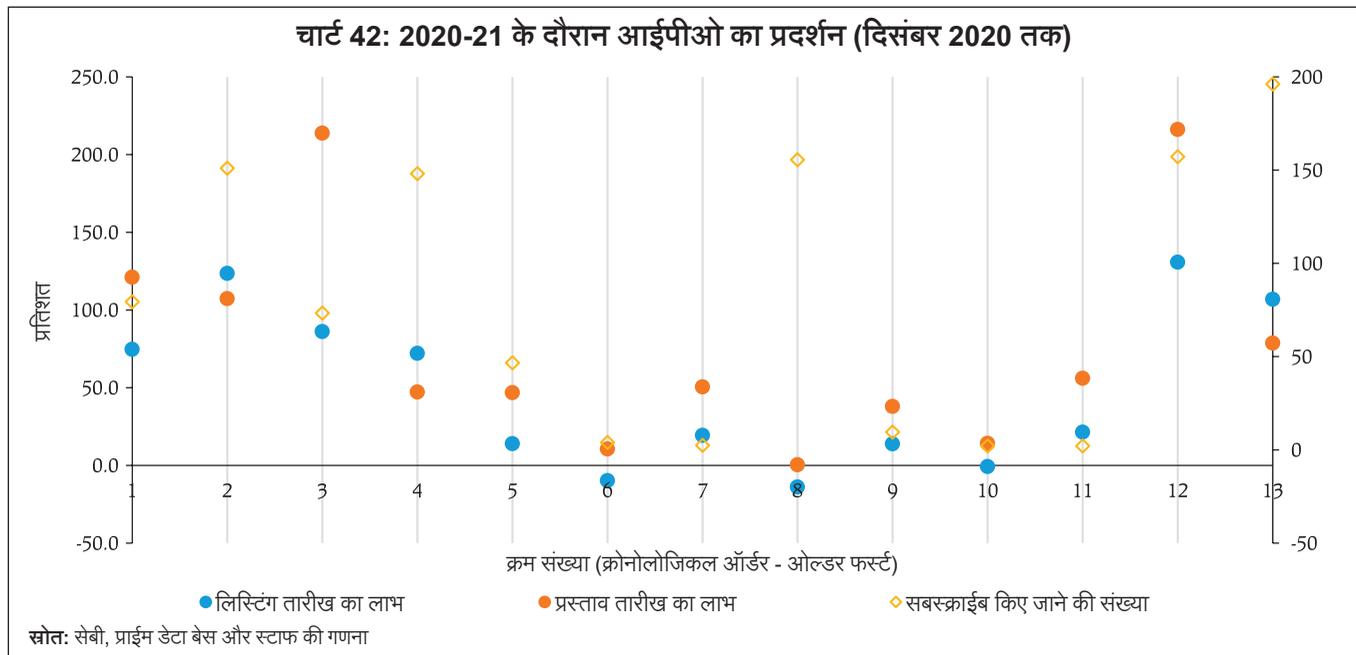


दिसंबर 2020 के दौरान ₹1,351 करोड़ रुपये के कुल दो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) की लिस्टिंग ने मुख्य बोर्ड आईपीओ के माध्यम से 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) में कुल ₹15,971 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹10,487 करोड़ रुपये से तेज उछाल दर्शाता है

(चार्ट 41)। जुलाई 2020 में जारी किए गए पहले आईपीओ ने, स्वास्थ्य सेवा और वित्त क्षेत्र की कंपनियों ने सभी प्रारंभिक प्रस्तावों में अधिकतम राशि जुटायी है।

खुदरा भागीदारी और उच्च प्रणाली-व्यापी चलनिधि में वृद्धि से निवेशकों को शानदार रिटर्न देने में आईपीओ को मदद मिली,





13 में से 10 आईपीओ को लिस्टिंग दिवस पर सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ है और सभी आईपीओ को लिस्टिंग दिवस पर तारीख आधार प्रस्ताव पर सकारात्मक आय प्राप्त हुई है (चार्ट 42)। इसके अलावा, अधिकतर आईपीओ लिस्टिंग दिन के बाद में भी तेजी आई।

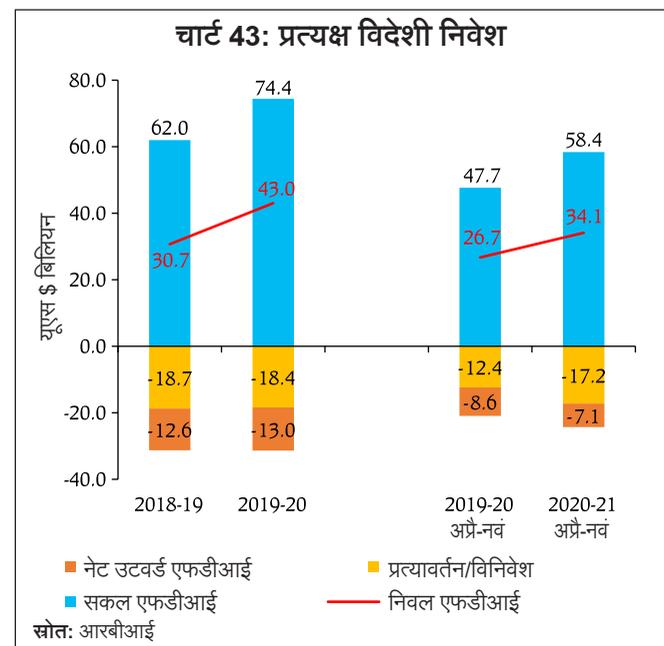
निवेशकों के लिए आईपीओ के लिस्टिंग दिन की आय (-) 14.0 प्रतिशत और 130.7 प्रतिशत के बीच रही। क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और रसायन क्षेत्र में निवेशकों को उच्चतम कमाई हुई (सारणी 6)।

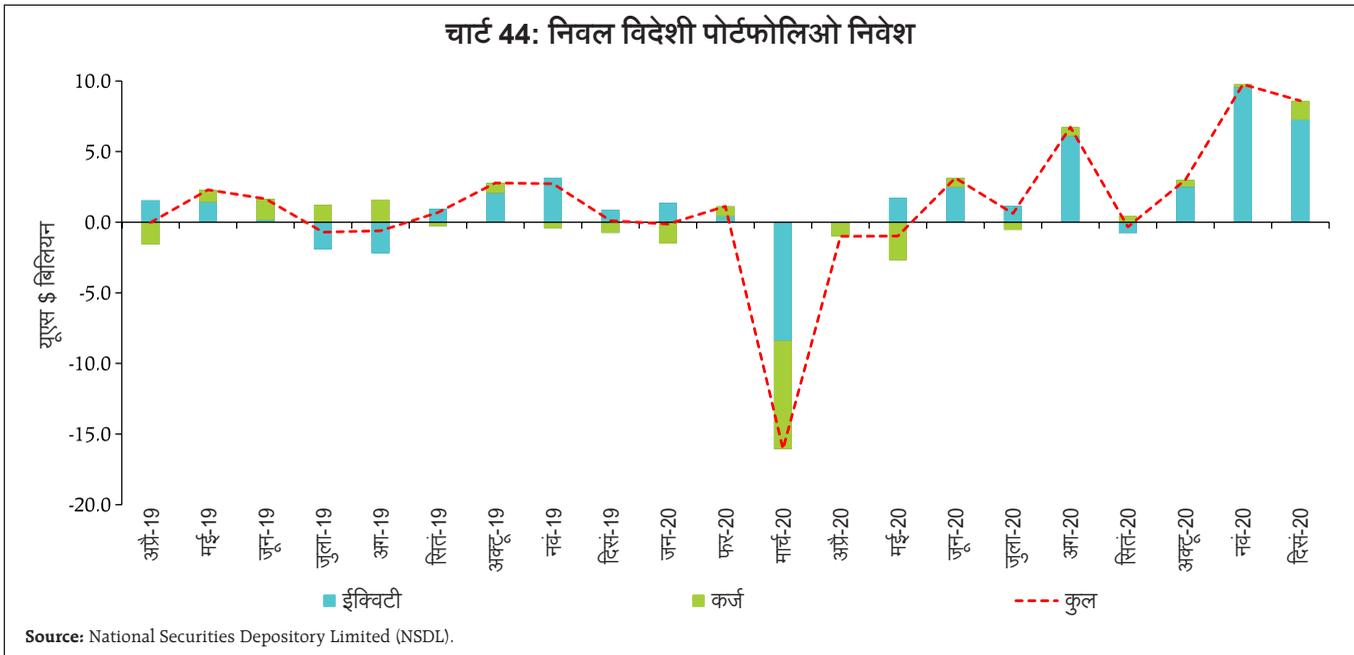
नये इक्विटी निवेश के कारण अगस्त-नवंबर 2020 में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बढ़ा है। फलस्वरूप, अप्रैल-नवंबर 2020 में निवल एफडीआई पिछले वर्ष के अमेरिकी डॉलर 26.7 से बढ़कर अमेरिकी डॉलर 34.1 बिलियन तक बढ़ गया (चार्ट 43)।

सारणी 6: आईपीओ सूचीबद्ध होने के दिन की आय (क्षेत्र-वार)

क्रम सं.	क्षेत्र	न्यूनतम	अधिकतम	माध्य
1	केमिकल्स	72.0	74.7	73.3
2	इंजीनियरिंग	13.8	19.3	16.6
3	फिनांस	-14.0	14.0	-2.7
4	हेल्थकेअर	21.4	21.4	21.4
5	आईटी	86.0	123.5	104.8
6	फुड प्रोसेसिंग	106.8	130.7	118.7

नवंबर 2020 में ऑल टाइम इंट्रा-महीने के उच्च स्तर के बाद दिसंबर 2020 में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह मजबूत रहा। इसका कारण सतत वैश्विक मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्ति में बहाली हो सकता है। दिसंबर 2020 में, 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई आगमन काफी हद तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर की

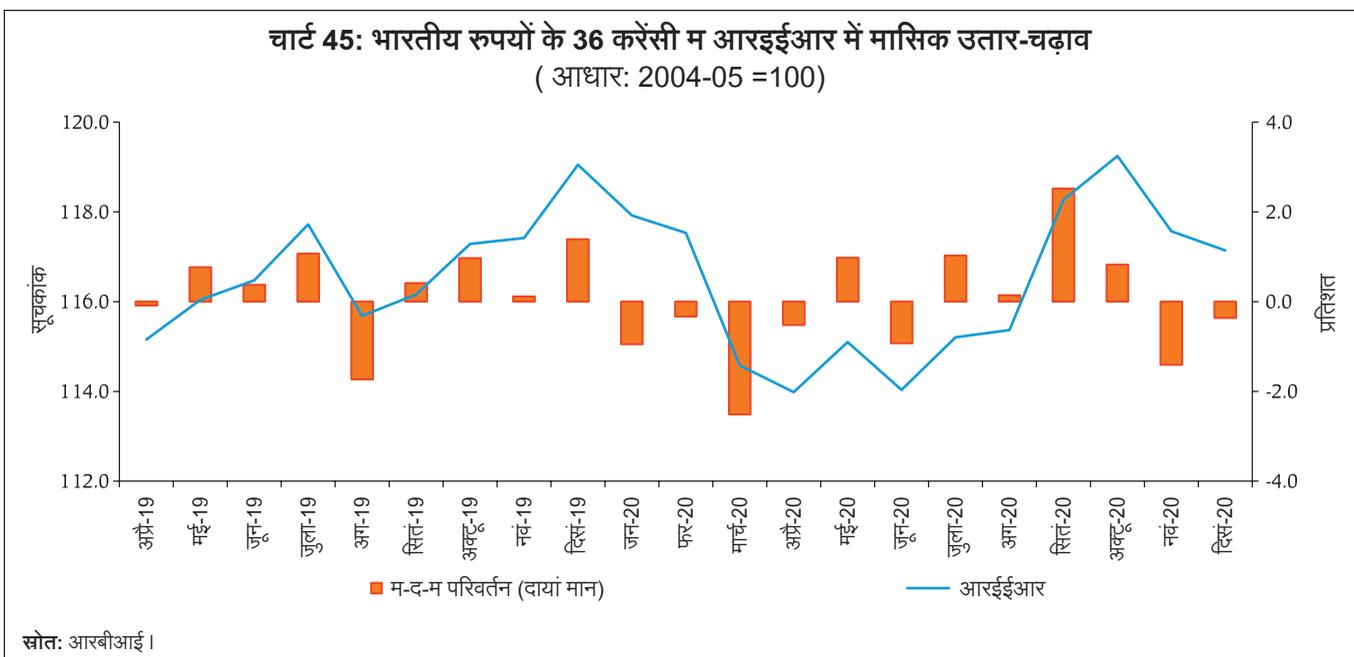




ईक्विटी खरीद से प्रेरित था। डेट सेगमेंट में, 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफपीआई आगमन, चालू वित्त वर्ष में अब तक की उच्चतम मासिक अभिवृद्धि है (चार्ट 44)। स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवल निवेश 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था।

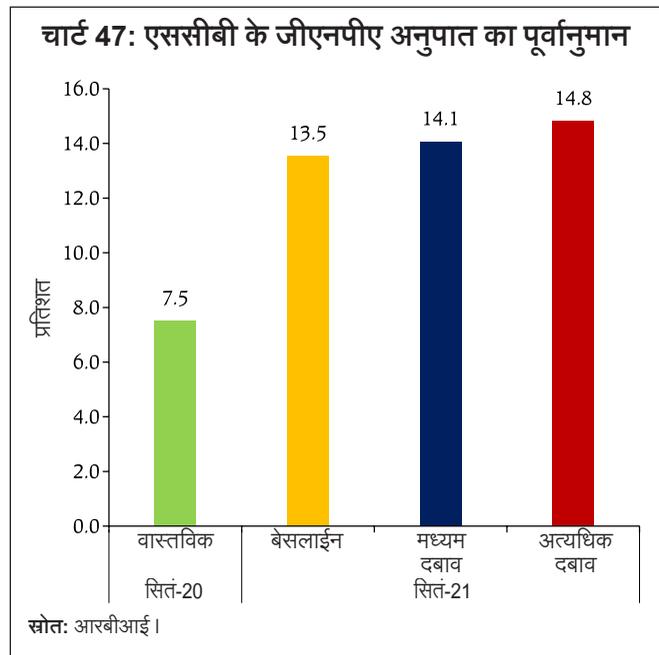
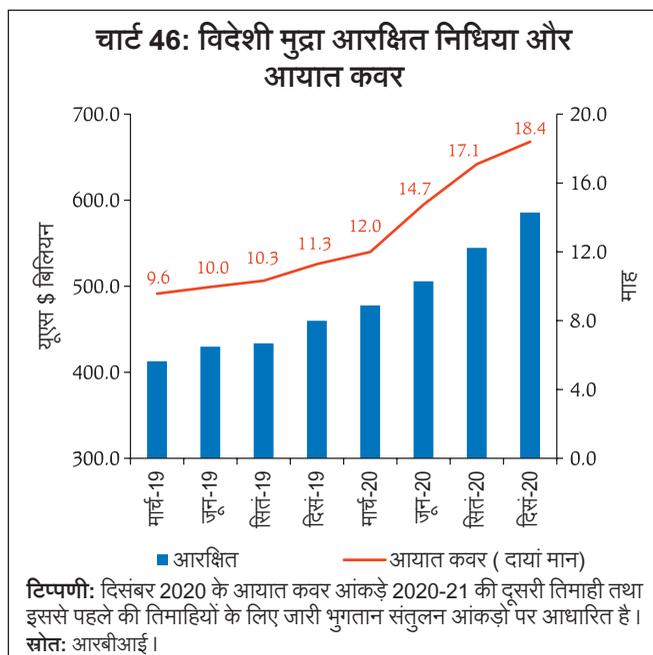
वैक्सीन समाचारों से विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (रुपये) ने मजबूत पूंजी प्रवाह से प्रभावित होकर, दिसंबर 2020

में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले महीने की तुलना में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2020 के अंत की स्थिति की के अपने स्तर से दिसंबर 2020 के अंत तक रुपये में 3.2 प्रतिशत वृद्धि हुई और अमेरिकी डॉलर की तुलना में ₹73.05 पर बंद हुआ, यह स्थिति आखिरी बार सितंबर 2020 की शुरुआत में देखी गयी थी (चार्ट 45)।



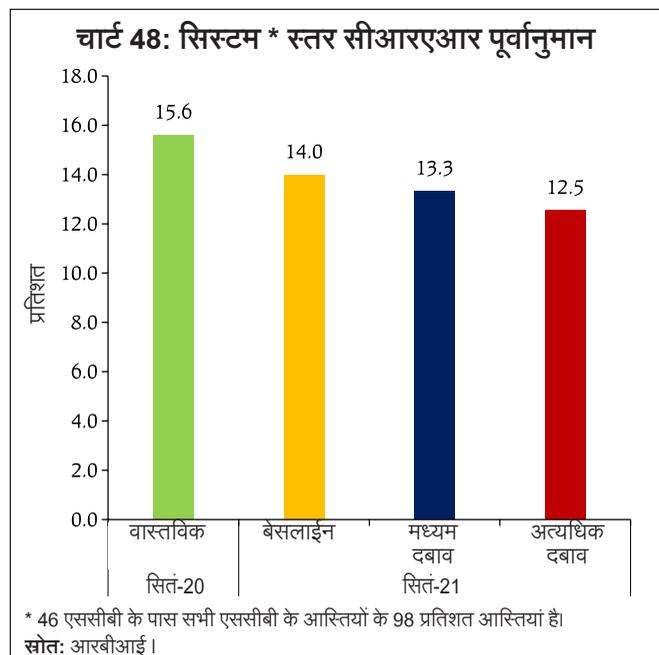
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 के अंत तक के भारत के विदेशी कर्ज के आंकड़े 31 दिसंबर 2020 को जारी किए गए थे। भारत का विदेशी कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बाहरी वाणिज्यिक उधार, पोर्टफोलियो कर्ज निवेश और अल्पकालिक व्यापार ऋण के कारण बाहरी कर्ज संतुलित रहा। दिसंबर 2020 के अंत तक, आरक्षित निधियों ने 585.8 बिलियन डॉलर का उच्च स्तर छू लिया, जो 18.4 महीनों के आयात के बराबर है या सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया बाहरी कर्ज का 105.3 प्रतिशत है (चार्ट 46)।

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विनियामक उपायों में ऋण आपूर्ति और प्रणालीगत लचीलापन बनाए रखते हुए आरक्षित वर्गों में आघात सहनशीलता आवश्यक है। सभी एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात में दिसंबर 2019 के 9.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत हो गया है, इसे विनियामक व्यवस्थाओं से काफी सहायता मिली। जनवरी 2021 की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में किए गए मैक्रो स्ट्रेस परीक्षणों से पता चलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सितंबर 2021 तक एससीबी का जीएनपीए अनुपात बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो सकता है, जो गंभीर



दबाव परिदृश्य के तहत बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 47)।

कुल स्तर पर, एससीबी के पास गंभीर दबाव परिदृश्य में भी पर्याप्त पूंजी कुशन ⁷ है (चार्ट 48)। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, कुछ



⁷ एससीबी द्वारा जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) में 9 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी बनाए रखना अपेक्षित है।

बैंकों के पूंजी बफर विनियामक न्यूनतम अपेक्षा से नीचे हो सकते हैं। इसलिए, आगे बढ़ते हुए, चरणवार पूंजी वृद्धि या अन्य कार्यनीतिक कार्रवाइयों जैसे कार्यों को कम करना इन बैंकों के लिए सूक्ष्म विवेकपूर्ण नजरिए से प्रासंगिक हो जाएगा।

नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर में सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान मामूली वृद्धि हुई; दूसरी ओर, अंतर-बैंक बाजार सिकुड़ने और बैंकों के पूंजीकरण के कारण बैंकिंग प्रणाली में मार्च 2020 की स्थिति की तुलना में संक्रमण का खतरा कम कर दिया।

भुगतान प्रणाली

भुगतान प्रणाली में, दिसंबर 2020 में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि जारी है, दोनों खुदरा और थोक लेनदेन में आर्थिक सुधार के व्यापक बेस के अनुरूप विस्तार हुआ। चूंकि थोक सेगमेंट में तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) को 14 दिसंबर 2020 से चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया था, इसकी मात्रा वृद्धि (वाई-ओ-वाई) तेजी से बदल गई और दिसंबर 2020 में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक महीने पहले 2.9 प्रतिशत थी। आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन का मूल्य, अक्टूबर 2019 के बाद से घटना शुरू हुआ था और महामारी में तेजी से घट गया था, दिसंबर 2020 में इसमें 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

रिटेल सेगमेंट में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) लेनदेन की मात्रा में दिसंबर 2020 में 31.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जबकि एक महीने पहले यह 24.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी। मूल्य के संदर्भ में, एनईएफटी लेनदेन क्रमशः 31.7 और 27.9 प्रतिशत बढ़ा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन मात्रा पिछले महीने के ऐतिहासिक 2.2 बिलियन से ऊपर बना हुआ है, जबकि लेनदेन मूल्य दिसंबर 2019 की तुलना में 105.5 प्रतिशत बढ़ गया है (सारणी 7)। तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से लेनदेन में वृद्धि हुई है, जिससे मात्रा और मूल्य वृद्धि दोनों में दोहरे अंकों का स्तर बढ़ गया है। नकदी आहरण भी बहाली की स्थिति में अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है।

सारणी 7: 2020-21 में भुगतान लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रैल-20	64,43,653	13,06,406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70,41,869	14,81,750	2,18,392	1,69,402
जून-20	86,51,978	19,06,586	2,61,835	2,06,951
जुलाई-20	83,35,279	19,63,113	2,90,538	2,25,775
अगस्त-20	72,92,380	19,30,552	2,98,308	2,35,137
सितंबर-20	94,89,066	21,65,515	3,29,032	2,48,662
अक्टूबर-20	84,96,046	22,35,389	3,86,107	2,74,645
नवंबर-20	79,87,655	22,18,252	3,90,999	2,76,459
दिसंबर-20	1,06,59,120	25,58,304	4,16,176	2,92,325

स्रोत: आरबीआई

बढ़ता हुआ ई-कॉमर्स, पेमेंट स्पेस में बिगटेक के बढ़ते पदचिह्न और बैंकों पर अपने भुगतान इको-सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए प्रतिस्पर्धी दबाव के साथ इस वर्ष डिजिटल पेमेंट की ओर प्राथमिकता बढ़ने का एक अलग पैटर्न स्पष्ट हो रहा है। कैशबैक, ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर छूट, आसान ईएमआई और अब खरीदे बाद में भुगतान करे जैसे प्रोत्साहन योजनाओं ने एक व्यापक ग्राहक बेस बनाया है। उन्होंने डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को भी बढ़ावा दिया है और खुदरा भुगतान प्रणालियों में लेनदेन की मात्रा को विशेष रूप से यूपीआई पर कर रहे हैं। चूंकि भुगतान उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, नए प्रतिभागी लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, भारत महामारी से पहले से कहीं अधिक डिजिटल उभर कर आ सकता है। यह उपभोक्ता खर्च को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था के औपचारिकता की डिग्री को बढ़ा सकता है।

रिजर्व बैंक ने अब अपने विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत 'क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स' इस विषय के दूसरे कोहार्ट की घोषणा की है। भारत दुनिया भर में इनबाउंड प्रेषण का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जो वैश्विक प्रवाह का 15 प्रतिशत का हिस्सेदार है। वर्ष 2019 में भारत को 83 अरब अमेरिकी डॉलर मिले थे और 2020 की पहली छमाही में 27.4 अरब अमेरिकी डॉलर मिले हैं। इस कोहार्ट से कम लागत, सुरक्षित, सुविधाजनक और पारदर्शी प्रेषण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का लाभ

उठाकर सीमा पार भुगतान परिदृश्य को फिर से ढालने में सक्षम नवाचारों को प्रेरित करने की उम्मीद है। नवाचार को प्रोत्साहित करने और पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाने के लिए प्रतिभागी संस्थाओं के लिए नेटवर्क आवश्यकताओं को ₹ 25 लाख रुपये से घटाकर ₹10 लाख रुपये कर दिया गया है, साझेदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को अब रुपये में भाग लेने की अनुमति है।

V. निष्कर्ष

वर्ष 2021 कैसे होगा? बहाली का आकार वी आकार होगा और ' वी ' का मतलब वैकसीन है। 16 जनवरी को, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी वैकसीन विनिर्माण क्षमता होने के अपने तुलनात्मक लाभ और पोलियो और खसरा के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीका अभियानों का एक समृद्ध अनुभव है। यदि सफल होता है, तो यह जोखिमों के संतुलन को ऊपर की ओर झुका देगा। ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियां विश्व के मुकाबले भारत की बहाली में उज्ज्वल स्थान होंगे, जिसमें निश्चित रूप से रिबाउंड होगा, लेकिन उत्पादन और रोजगार का महामारी पूर्व स्तर पाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। जापानिफिकेशन अधिकतम उन्नत दुनिया पर साफ झलकता है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, संभावित उत्पादन बहुत कम होगा।

मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य में हालिया बदलावों ने दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है, जीडीपी के साथ सकारात्मक क्षेत्र प्राप्त करने की दूरी और मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। यदि ये गतिविधि बनाए रखते हैं, तो बहाली का समर्थन करने के लिए नीतिगत स्थान खुल सकता है। घरेलू मांग की धीमी गति बहाली और निर्यात के अनलॉक होने के साथ, मर्केडाइज़ व्यापार जनवरी की शुरुआत में रिबाउंड हुआ। चालू खाता अधिशेष घरेलू गतिविधि के रूप में तेज़ हो रहे हैं। विदेशी निवेश प्रवाह पहले से ही आसन्न संकट को भांप रहा है। इक्विटी बाजारों द्वारा हाल ही में दर्ज नई उचाइयां, तीसरी तिमाही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, इंफोसिस और विप्रो जैसे आईटी कंपनियों में वृद्धि के कारण कॉर्पोरेट आय के परिणामों से प्रेरित हैं।

वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, जीडीपी वृद्धि सांख्यिकीय समर्थन से लाभान्वित होगी और ज्यादातर खपत-चालित होने की संभावना है। रबी की बुआई सीजन के अंत से पहले सामान्य क्षेत्रफल पार करने से, 2021 में बम्पर कृषि उत्पादन की उम्मीद है। भारत वैकसीन विनिर्माण के लिए वैश्विक पूंजी राजधानी होने के नाते, फार्मास्यूटिकल्स निर्यात को विश्व स्तर पर टीकाकरण अभियानों की शुरुआत के साथ एक बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। कृषि निर्यात लचीला बना हुआ है और हाल ही में उत्पादन लिंकड (पीएलआई) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कम मूल्य वाले अर्ध-प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों में बदलाव करके सहक्रियाओं का उपयोग करने से न केवल उत्पादकता में सुधार होगा बल्कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2020 में विकास ने खपत की मांग को मजबूत करने और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बढ़ते व्यापार लेनदेन के पीछे एक नए डिजिटल परिवर्तन का सूत्रपात किया है। विश्व आर्थिक मंच की 7 जनवरी 2021 को जारी रपोर्ट इंडियन सिटीज इन द पोस्ट पेनडेमिक के अनुसार - महामारी बेहतर नया शहरी प्रतिमान बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करती है - जो भारतीय शहरों को स्वस्थ, अधिक समावेशी और अधिक लचीला बनाने में सक्षम बनाता है। शहरी सुधार एजेंडा सात विषय यथा योजना; आवास; परिवहन; वातावरण; सार्वजनिक स्वास्थ्य; लिंग; और कमजोर आबादी के अनुरूप स्थापित किया जा सकता है।

स्थायी विकास तथा एक स्थिर बदलाव के लिए तत्काल किकस्टार्ट निवेश की आवश्यकता है। भारत को ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए, जिसमें कॉरपोरेशन और बैंकों की बैलेंस शीट में नकद रूप से बैठे और रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो बैलेंस, उत्पादक क्षेत्रों के लिए क्रेडिट में और निवेश गतिविधि पर वास्तविक खर्च करने से पहले वास्तविक गतिविधि में लगातार अपक्षय भार वहन करने के तरीके का पता लगाएं। भारत को ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए, जिसमें कॉरपोरेशन और बैंकों की बैलेंस शीट की निष्क्रिय नकद और रिज़र्व बैंक के रिवर्स रेपो बैलेंस, यह वास्तविक गतिविधि पर लगातार अपस्फीति भार

लगाने से पहले, उत्पादक क्षेत्रों के लिए कर्ज देने में और निवेश गतिविधि पर वास्तविक खर्च के लिए काम आए। वित्तीय क्षेत्रों की बैलेंस शीट में तनाव, अधिस्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव तथा कमजोर पुनर्गठन के रूप में तेज हो सकता है, लेकिन बैंकों ने वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में मजबूत पूंजी बफर्स के साथ स्वास्थ्य संकट में प्रवेश किया है। स्लिपेज अनुपात कम हो रहा है और ऋण वसूली में सुधार हो रहा है तथा प्रावधान कवरेज अनुपात में भी 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। पूंजी लगाना और ऋण अपचार से निपटने के अभिनव तरीकों पर नीति का ध्यान केंद्रित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसांख्यिकीय लाभांश फिसलने के पहले वित्त के माध्यम से वृद्धि को टिकाऊ आधार पर निर्बाध बनाया जा सके। अर्थव्यवस्था को ठीक होने में कई साल लगेंगे, लेकिन अभिनव दृष्टिकोण महामारी को अवसरों में बदल सकते हैं। क्या केंद्रीय बजट 2021-22 गेम-चेंजर होगा?

संदर्भ:

Agarwal, R., Padhi, I., Goyal, S., Behera, S.R. and Misra, S. 'Government Finances 2020-21: A Half-Yearly Review', *RBI Monthly Bulletin*, December 2020.

Covid-10 trn. (January 9-15, 2021). *The Economist*.

Financial Stability Report. (Issue No. 22, 2021). *RBI*.

Global Economic Prospects. (January 2021). *World Bank*.

IIF Capital Flows Tracker – December 2020. (January 2021). *Back from the Brink*.

Kumar, P. 'An Economic Activity Index for India', *RBI Monthly Bulletin*, November 2020.

Reinhart, C., 'The coming COVID-19 Credit Crunch', *World Bank Blogs*, December 2020.

Sedik, T.S. and Xu, R., 'A Vicious Cycle: How Pandemics Lead to Despair and Economic Unrest?', *IMF Working Paper*, October 2020.

Shahidi T., Dantewadia P., (2021, January 05), 'State Recovery Tracker: UP, Rajasthan, other large states led economic recovery in December'. *Livemint*.

State Finances: A Study of Budgets of 2020-21. (2020). *RBI*.